RNI .NO. MPBIL / 2013/ 54381

संपादकः- डॉ. देवेन्द्र मालवीय

12 वर्ष

दैनिक
सद्भावना पाती

...प्राणियों में सद्भावना हो...

www.sadbhawnapaati.com Email: sadbhawnapaatinews@gmail.com इंदौर, बुधवार ●31 जुलाई , 2024 वर्षः-12 अंक-94 मूल्य -1 रु. कुल पृष्ठ - 8

प्रदेश में अब आधी कीमत में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर

भोपाल। रक्षाबंधन से ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। अभी मध्य प्रदेश गैस सिलेंडर 848 रुपए का है, इस लिहाज से करीब आधी कीमत ही उन्हें चुकानी होगी। प्रति सिलेंडर 399 रुपए का खर्च राज्य सरकार की ओर से उठाया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

मोहन सरकार ने 'लाडली बहना' को दे दिया नया तोहफा

ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा, लाडली बहना योजना के तहत हमने फैसला किया है कि इस योजना की सभी लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दें। गैस की टंकी अभी 848 रुपए में मिल रही है। इसमें 450 रुपए लाडली बहनों को देना होगा। 399 रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार देगी। इसमें करीब 160 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लाडली बहना योजना के तहत अभी राज्य की लाखों महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 1250 रुपए राज्य सरकार की ओर से जमा किए जाते हैं। इस बार रक्षाबंधन की वजह से सरकार 250 रुपए अतिरिक्त देगी। इसका भुगतान 1 अगस्त को किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। 2023 में भाजपा को मिली रिकॉर्ड जीत में इस योजना को अहम माना जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला किया है। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण योजना के तहत आंगनवाड़ी की सभी बहनों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवर किया जाएगा। इसका प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। प्रदेश की 57 हजार 324 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। विजयवर्गीय ने बताया कि एमपी रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत गांव को शहरों से जोड़ने के लिए जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट रह गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। जितनी राशि केन्द्र से मिलेगी,उतनी ही राज्य सरकार मिलाएगी।

संक्षिप्त समाचार

'ब्लेम गेम' के शोर के बीच धुंधली हो जाएगी दिल्ली की कहानी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर में हुए हादसे को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। इस बीच गृह मंत्रालय ने घटना की जांच के लिए एक हाई-लेवल कमेटी गठित कर दी है। संसद में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ने आम आदमी पार्टी को घटना का

जिम्मेदार बताया तो वहीं विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोचिंग सेंटरों की संस्कृति किसी 'गैस चैंबर' से कम नहीं हो गई है। इस दौरान उन्होंने कोचिंग संस्थानों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है।

वजन घटाने वाले अमेरिकी इंजेक्शन को भारत में मंजूरी

अहमदाबाद (एजेंसी)। कॉमनमैन के इर्द-गिर्द दो सवाल घूमते हैं। 1. तेजी से पैसा कैसे कमाए। 2. वजन कैसे कम करें। हम पहले प्रश्न का उत्तर कुछ समय बाद एक लेख में देने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम दूसरे प्रश्न का उत्तर यहां देंगे। भारत की बात छोड़िए, अगर

हम गुजरात की ही बात करें तो यहां मोटे लोगों की भरमार है। पुरुष पिलपिले होते हैं, कमर के बाहर चर्बी लटकी रहती है, महिलाओं में भी मोटापा अधिक होता है। एक बार जब शरीर मोटा हो जाता है तो कई अन्य बीमारियां भी घेर लेती हैं। वजन कम करने के केवल दो ही तरीके हैं। घूमना और डाइटिंग करना। अब एक तीसरा और आसान रास्ता खुल गया है।

राजस्थान के विधायकों की सैलरी हर साल 10 फीसदी बढ़ेगी

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान में विधायकों के वेतन, भत्ते और पूर्व विधायकों की पेंशन अब सरकारी कर्मचारियों की तरह हर साल बढ़ेगी। इसके लिए हर बार विधानसभा में बिल पास नहीं करवाना होगा। सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में बजट पास होने से पहले फाइनेंस और एप्रोप्रिएशन बिल (वित्त एवं विनियोग विधेयक) पर हुई बहस का

जवाब देते हुए इसकी घोषणा की है। सीएम भजनलाल ने कहा- कई विधायकों और पूर्व विधायकों ने वेतन और पेंशन को लेकर उनसे आग्रह किया था। विधायकों के वेतन और पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होगी, यह आगे तय होगा। कम से कम 10 प्रतिशत सालाना का इजाफा तय माना जा रहा है।

केरल के वायनाड में लैंड स्लाइड, 93 लोगों की मौत

आधी रात को मौत ने मचाया तांडव, 400 लोग लापता, 4 गांव बहे

सेना बुलाई गई, बारिश की वजह से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लौटा

वायनाड़ (एजेंसी)। वायनाड में आधी रात को तीन बार हुए लैंडस्लाइड से हर तरफ तबाही है। मौतों का आंकड़ा 93 के पार पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने मृतकों और घायलों की मदद का ऐलान किया है। केरल के वायनाड में भारी बारिश के चलते मंगलवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। तीन जगहों पर भूस्खलन के चलते अब तक 93 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा करीब 100 लोग घायल हैं, जिन्हें निकाला गया है। इन भूस्खलनों की वजह बीते 2-3 दिनों से जारी भारी बारिश है। इतनी भारी मात्रा में अचानक हुई बारिश से मिट्टी कटती चली गई और फिर इतना बड़ा हादसा ढाई बजे रात को हुआ, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। अब इस हादसे के कारणों का एक्सपर्ट पता लगा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायनाड के जिस मेप्पादी इलाके में लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, वहां बड़े पैमाने पर मिट्टी का क्षरण बीते कुछ सालों में हुआ है। इसके चलते यह हादसा हुआ है और अचानक मिट्टी खिसक गई। दरअसल बीते कुछ सालों में इस इलाके से पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटा गया है। इस वन क्षेत्र में बड़े वृक्षों को काटकर फसलें उगाने की कोशिशें हुई हैं। इसके चलते मिट्टी का क्षरण तेजी से हुआ है और लैंडस्लाइड जैसी घटना हो गई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भले ही कई दिनों से चल रही भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है, लेकिन ऐसे हादसों की भूमिका मिट्टी के क्षरण से ही तैयार हुई थी।

सरबजोत का मिला साथ और रच दिया इतिहास

● पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत को दिलाया दूसरा मेडल ● एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनीं

पेरिस (एजेंसी)। भारतीय जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलिंपिक में इतिहास रच दिया है। मनु और सरबजोत ने शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत के शूटरों ने ली वोन्हो और ओह ये जिन की कोरियाई जोड़ी को हराया। इससे पहले रविवार को मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ओलिंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी थी, जबकि अब वह एक ही ओलिंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। भारतीय स्टार जोड़ी ने साउथ कोरिया की ली ओन्हो और ओह ये जिन की जोड़ी को 16-10 के बड़े अंतर से हराया। यह भारत के लिए ऐतिहासिक पल है। शूटिंग में इससे पहले किसी शूटर ने दो मेडल नहीं जीते थे, लेकिन मनु ने कमाल कर दिया है। इस तरह से मनु भाकर आजादी के बाद एक ही ओलिंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। अभी मनु 25 मीटर इवेंट में भी मेडल की दावेदारी पेश करेंगी। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश मूल के भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड ने 1900 ओलिंपिक में 200 मीटर फर्राटा और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीते थे लेकिन वह उपलब्धि आजादी से पहले की थी। पदक जीतने के बाद सरबजोत सिंह ने बताया कि यह गौरव का पल है।

मालगाड़ी से टकराने के बाद बेपटरी हुई हावड़ा-मुंबई मेल

18 डिब्बे पटरी से उतरे, अब तक 2 की मौत, 20 घायल

जमशेदपुर (एजेंसी)। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह 3.43 बजे 12810 मुंबई-हावड़ा मेल पहले से डिरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के बाद मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन का इंजन डिरेल हुई मालगाड़ी की बोगी से टकराया। इसके बाद ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा राजखरसवां और बड़ाबाम्बो के बीच हुआ। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा देना का ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि रेलवे की दुर्घटना राहत ट्रेन और एंबुलेंस घटनास्थल पर मौजूद है। घायलों को चक्रधरपुर स्थित रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दुर्घटना की पुष्टि करते हुए चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने कहा कि घटना की सूचना के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारी चक्रधरपुर रेल मंडल से रिलीफ ट्रेन और जिला प्रशासन के द्वारा तमाम एंबुलेंस घटनास्थल की ओर से रवाना हो चुकी हैं। वहीं इस घटना को लेकर रेलवे ने 0651-27-87115 नंबर जारी किया गया है। इस घटना के चलते दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर-चक्रधरपुर खंड पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है। इस हादसे के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। रेलवे अधिकारी पटरी की मरम्मत और ट्रेन परिचालन बहाल करने के काम में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हावड़ा से चलकर मुंबई जाने वाली मुंबई मेल सोमवार रात 11 बजकर दो मिनट के बजाए दो बजकर 37 मिनट पर टाटानगर पहुंची थी और दो मिनट के स्टॉपेज के बाद चक्रधरपुर के लिए चल पड़ी लेकिन यह ट्रेन अपने अगले स्टेशन तक पहुंचती, उससे पहले सुबह तीन बजकर 45 मिनट पर बाराबम्बों स्टेशन से आगे जाकर दुर्घटना का शिकार हो गई।

किसानों को दूध पर प्रति लीटर बोनस देने की तैयारी

अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी संभव, ढाई लाख किसान सोसायटी में बेचते हैं दूध

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बोनस या इंसेटिंव के रूप में किसानों को राशि देने की तैयारी में है। यह बोनस प्रति लीटर दूध पर दिया जाएगा। जिसके लिए पशुपालन विभाग परियोजना परीक्षण समिति से अंतिम निर्णय लेकर प्रस्ताव शासन को भेजेगा। इसके बाद कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार ढाई लाख किसानों से सोसायटी से दूध की खरीदी करती है, और बोनस का फायदा इन किसानों को होगा। सीएम मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले गुजरात का दौरा कर वहां अमूल डेयरी के अफसरों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में एमपी के दूध उत्पादन को बढ़ावा देने पर अमूल ग्रुप के साथ चर्चा के बाद एक एमओयू भी हुआ था।

इसके उपरांत सीएम मोहन यादव ने दूध का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अफसरों को दूध पर बोनस या इंसेंटिव देने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। अब यह प्रस्ताव तैयार हो गया है, और जल्दी ही मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया

जाएगा। एमपी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन के एमडी सतीश कुमार एस. ने कहा- किसानों को इंसेटिव देने की प्लानिंग चल रही है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में ही होगा। तभी इसकी वस्तु स्थिति और कितना इंसेंटिव दिया जाएगा।

सागर संभाग में एक लाख लीटर दूध की खरीदी

सागर जिले के सिरोंजा में बुंदेलखंड विकास पैकेज के अंतर्गत डेयरी प्लांट स्थापित है। इस प्लांट के लिए सागर संभाग के सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी दमोह जिले से रोजाना करीब एक लाख लीटर दूध खरीदा जाता है। उधर, ग्वालियर-चंबल संभाग में मुरैना जिला सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक जिलों में शामिल है। जिलों में दूध कलेक्शन दुग्ध सहकारी समितियां और दुग्ध संघ करते हैं। प्रदेश में 7000 ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियां हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 6 सहकारी दुग्ध संघ है जिनके मुख्यालय भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर एवं सागर में हैं। राज्य स्तर पर एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (एमपीसीडीएफ) कार्यरत हैं जो इसकी मॉनिटरिंग करता है।

मैं महापौर बोल रही हूं-जिंसी चौराहे से अतिक्रमण हटाएं

● पहले भी ठेले हटाने को कहा था; महिलाएं-बच्चों को निकलने में परेशानी हो रही

भोपाल। मैं महापौर मालती राय बोल रही हूं...। जिंसी चौराहे पर अतिक्रमण है। कई ठेले बीच में ही खड़े हो जाते हैं। इससे बच्चों और महिलाओं को गुजरने में दिक्कतें होती हैं। पास में ही सेंट फ्रांसिस स्कूल है। पहले भी ठेले हटाने को कहा था। ये वापस क्यों आ जाते हैं। आगे ऐसा न हो। भोपाल के स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से मंगलवार को महापौर राय ने मोबाइल पर अफसरों को कॉल करके कुछ इस तरह से निर्देश दिए। यहां महापौर ने महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा की और हर विभाग के

जिम्मेदारों को कॉल करके पेंडिंग शिकायतों के बारे में बताया। महापौर ने उद्यान, सिविल, गोवर्धन परियोजना, अतिक्रमण, सफाई, स्ट्रीट लाइट, सीवेज, स्ट्रीट डॉग्स प्रभारी को भी कॉल किया। महापौर ने बताया कि अब तक कुल 4143 शिकायतें आई हैं।

लोकसभा में उठा यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का मामला

भोपाल सांसद ने कहा-मार्च 2023 में केंद्र से 126 करोड़ मिले फिर भी कचरा नहीं उठा

भोपाल। लोकसभा में मंगलवार को भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भोपाल की यूनियन कार्बाइड परिसर में 40 साल से पड़े जहरीले कचरे का निष्पादन न होने का मामला उठाया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान आलोक शर्मा ने कहा- मैंने 2-3 दिसंबर की रात को हुई दुनिया की सबसे भीषणतम त्रासदी को झेला है। ये देश का महत्वपूर्ण मुद्दा है। शून्यकाल में आलोक शर्मा ने कहा- मैं यूनियन कार्बाइड की

भीषणतम त्रासदी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह भोपाल ही नहीं देश का महत्वपूर्ण मुद्दा है। 2 दिसंबर 1984 की रात 1.00 बजे पूरा भोपाल गहरी नींद में सो रहा था और सोते समय अचानक लोगों को खांसी होने लगी और इस घटना में हजारों लोग मौत की आगोश में सो गए थे। उस मौत के मंजर को मैंने अपनी आंखों से देखा है।

प्रदेश पाती
दैनिक सद्भावना पाती
इंदौर, बुधवार 31 जुलाई , 2024

सरकार की 125 योजनाओं के बंद होने का खतरा! वित्त विभाग के इस आदेश से मचा हड़कंप

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का ऋण है कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार की कई योजनाओं पर अब खतरा मंडरा रहा है दरअसल, वित्त विभाग ने लाड़ली लक्ष्मी समेत 125 योजनाओं के फंड जारी करने को लेकर एक तरह से रोक लगा दी है वित्त विभाग की परमिशन के बिना अब ऐसी योजनाओं की राशि जारी नहीं की जा सकेगी लाड़ली लक्ष्मी योजना जैसी मध्य प्रदेश सरकार की लगभग 125 योजनाएं ऐसी हैं, 47 विभागों की, जिस पर वित्त विभाग ने एक तरह से रोक लगा दी है वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है दरअसल, वित्त विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि इन 125 स्कीमों के लिए जो पैसा खर्च होगा, वह बिना वित्त विभाग की अनुमति से या उसके डायरेक्ट परमिशन लेनी होगी, उसके बगैर नहीं किया जाएगा।

लाड़ली बहना योजना सरकार की टॉप प्रायोरिटी

मध्य प्रदेश सरकार लगभग 1600 करोड़ रुपये हर महीने लाडली बहनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देती है हर महीने लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपये डाले जाते हैं लाड़ली बहना योजना पर फिलहाल किसी तरह का खतरा नजर नहीं आ रहा है, चूंकि इसकी राशि के लिए वित्त विभाग की परमिशन की जरुरत नहीं है तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या लाडली बहना योजना ही सरकार की टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि लाडली बहना योजना के ऊपर इस तरह की बंदिशें नहीं लगाई गई है क्या सरकार लाडली बहनों से आगे सोच नहीं पा रही है? क्या लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक लायबिलिटी बनता जा रहा है वित्त विभाग द्वारा इन योजनाओं के फंड पर परमिशन लेने के

आदेश के बाद चर्चा होने लगी है क्या ये योजनाएं बंद हो जाएंगी? सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित का इसे लेकर कहना है कि वित्त विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्कीम को स्टॉल कर दिया गया है या रोक दिया गया है लेकिन अगर उस समय पैसा मौजूद नहीं है, तो हो सकता है मना भी कर दिया जाए, इसीलिए शायद परमिशन लगाई है मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति सरकार की ठीक नहीं है औसत हर महीने 2000 करोड़ का कर्ज सरकार ले रही है और करीब 4 लाख करोड़ का बजट है और उतना ही कर्जा पहुंच गया है।

संक्षिप्त समाचार

कोलार डैम के 02 गेट खोले गए

सीहोर (निप्र)। कोलार परियोजना अंतर्गत कोलार डैम वीरपुर का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोलार डैम में पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के दो गेट खोले गए हैं। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह एवं कोलार नहर संभाग की कार्यपालन यंत्री सुश्री हर्षा जैनवाल ने आमजन अपील की है कि कोलार नदी, कोलार नहर तथा कोलार बांध के प्रभावित क्षेत्र में न जाएं तथा सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।

कलेक्टर सिंह ने अतिवर्षा से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव चौकसे के साथ खिरकिया क्षेत्र के ग्रामों का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान ग्राम पहटकला और रोलगांव में पुलिया से वर्षा के पानी के ओवरफ्लो के कारण उत्पन्न स्थिति को देखा और होमगार्ड, राजस्व तथा पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पुल पुलियों के दोनों और बेरीकेटिंग करवाई जाए और वहां पर चौकीदार तैनात किए जाएं ताकि किसी दुर्घटना की आशंका न रहे। इस दौरान एसडीएम खिरकिया श्री संजीव नागू तथा होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट श्री मयंक जैन भी मौजूद थे।

अति-दुर्लभ रक्त ग्रुप दान से गर्भवती महिला को मिला नया जीवन

विदिशा (निप्र)। विदिशा के कुंआ खेड़ी निवासी गर्भवती महिला श्रीमती सुरक्षा मीना को अति दुर्लभ रक्त ग्रुप एबी निगेटिव की आवश्यकता थी। सूचना मिलने पर मध्यप्रदेश रक्त सहायता समिति के प्रांतीय पदाधिकारी श्री मनोज कपूर हांसुआ ने रक्तदान कर महिला को जीवन दान दिया है। एबी निगेटिव रक्त ग्रुप अति-दुर्लभ श्रेणी में आता है, जो लगभग एक लाख व्यक्तियों में मात्र दो-तीन व्यक्तियों में ही पाया जाता है। समिति के प्रांतीय पदाधिकारी श्री कपूर ने आज अपने पिता की पुण्य स्मृति में रक्तदान कर गर्भवती महिला का जीवन बचाया है। आज ही के दिन श्री कपूर के पिता स्वर्गीय श्री बृजमोहन कपूर का पुण्य स्मरण दिवस है। मध्यप्रदेश रक्त सहायता समिति के चैयरमेन श्री उदय सिंह हजारी सहित समिति के अन्य पदाधिकारीयों ने अति दुर्लभ रक्त ग्रुप एबी निगेटिव का रक्तदान कर गर्भवती महिला को जीवन दान देने के लिए उनके प्रति साधुवाद अभिव्यक्त किया है।

सीएम हेल्पलाइन में जिला पंचायत ए ग्रेड के साथ प्रदेश में द्वितीय स्थान पर

विदिशा (निप्र)। सीएम हेल्पलाइन (181) में दर्ज शिकायतों के निराकरण मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जिला पंचायत विदिशा द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव ने प्रशंसा पत्र प्रेषित कर जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर योगेश भरसट के मार्गदर्शन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अमले द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की है। जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर भरसट के मार्गदर्शन में जिला पंचायत विदिशा के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुये माह जून 2024 में 52.2 प्रतिशत संतुष्टि वेटेज एवं 87.84 प्रतिशत कुल वेटेज प्राप्त कर ष्एष् ग्रेड के साथ प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। विभागीय प्रदर्शन में सराहनीय योगदान के फलस्वरूप विभागवार ग्रेडिंग में विभाग उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ द्वितीय स्थान पर रहा है।

जनसुनवाई कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करें

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने हरेक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें के निर्देश लंबित आवेदनो की समीक्षा बैठक में दिए है। उन्होंने कहा कि कलेक्टेऊट के भूतल स्थित सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू हो जाता है दूरदराज से आने वाले आवेदको की समस्याएं त्वरित निदान हो कि पहल करें ऐसे आवेदन जिनका निराकरण जिला स्तर पर संभव नहीं है कि जानकारी आवेदक के संज्ञान में लाते हुए विभाग प्रमुख को प्रेषित करें और जब तक आवेदन का समाधान नहीं हो जाता है। पत्राचार अथवा टेलीफोनिक सम्पर्क बनाए रखे ताकि निराकरण की जानकारी जन आकांक्षा पोर्टल पर दर्ज की जा सकें।

जिला अस्पताल में भारी अव्यवस्थाः मरीजों के लिए जमीन में लेटने के लिए भी नहीं है जगह

अस्पताल से बाटल चढ़ाने वाले स्टैण्ड भी गायब, मरीज हो रहे पेरशान

पन्ना। जिला चिकित्सालय पन्ना की अव्यवस्था लगातार सामने आ रही है। वर्तमान समय में बीमारियों का सीजन तो है ही जिससे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन जिला चिकित्सालय प्रबंधन की अव्यवस्था भी देखी जा रही है। डिलेवरी वार्ड में पन्द्रह पलंग मरीजों के लेटने के लिए हैं तथा नीचे भी कुछ मरीजों को लेटाया गया है। एक-एक पंलग पर दो-दो मरीज भी देखे जा रहे हैं तथा वार्ड के अन्दर एक सैकड़ा से अधिक मरीजों की भीड़ भरी हुई है।

उक्त वार्ड में मरीजों को वाटल लगाने के लिए स्टैण्ड भी नसीब नहीं हो रहे हैं। दूसरी ओर भारी गर्मी व उमस का मौसम चल रहा है। उसके बावजूद कूलर एवं पंखों की हालत भी बदतर है। कूलर बंद हैं, पंखा भी शोपीस बने हुए हैं। वारिस होने पर अनेक वार्डों में भारी मात्रा में पानी भर जाता है। जिसके कारण मरीजों को जमीन पर बैठना भी मुश्किल हो जाता है।

सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सबसे अधिक बजट उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से जिला अस्पताल में अव्यवस्था देखी जा रही है उससे यह लगता है कि आखिर सरकार का बजट जिम्मेवार जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन कहां खर्च कर रहे हैं। पन्ना जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार मीडिया द्वारा भी उछाला जा रहा है उसके बावजूद जिले के वरिष्ठ अधिकारियों तथा जिम्मेवार जनप्रतिनिधियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही।

घायल शावकों को बचाने के सीहोर जिला प्रशासन के प्रयासों को मुख्यमंत्री ने बताया वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता

सीहोर (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यह हमारा सौभाग्य है कि मध्यप्रदेश सर्वाधिक बाघ वाला प्रदेश है। प्रदेश में बाघों की आबादी बढ़कर 785 पहुँच गई है। यह प्रदेश के लिये गर्व की बात है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा का कार्य अत्यंत मेहनत और परिश्रम का है। समुदाय के सहयोग के बिना वन्य प्राणियों की सुरक्षा संभव नहीं है।

वन विभाग और वन्य प्राणियों की सुरक्षा में लगे सभी लोग बधाई के पात्र हैं, जिनके कारण मध्यप्रदेश एक बार फिर टाइगर स्टेट बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जंगलों में बाघों के भविष्य को सुरक्षित करने और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लेने का आहवान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बाघों के संरक्षण के लिये संवेदनशील प्रयासों की आवश्यकता होती है जो वन विभाग के सहयोग से संभव हुई है। हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में बेहतर प्रबंधन से जहाँ एक ओर वन्य प्राणियों को संरक्षण मिलता है, वहीं बाघों के प्रबंधन में लगातार सुधार भी हुए हैं।

वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता

वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता का हाल ही में सीहोर जिले में एक उदाहरण सामने आया था। सीहोर जिले के बुदनी के मिडघाट रेलवे ट्रेक पर बाघिन के तीन शावक ट्रेन की चपेट में आ गये थे, जिसमें दो गंभीर रूप से घायल शावकों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर जिला प्रशासन और वन्य प्राणी चिकित्सकों की टीम द्वारा एक डिब्बे की विशेष ट्रेन से उपचार के लिये भोपाल लाया गया था।

पीएम जनमन योजना के कार्यो की समीक्षा

विदिशा (निप्र)। 1कलेक्टर श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने सोमवार को लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान जिले में क्रियान्वित पीएम जनमन योजनाओं के कार्यो का भी जायजा लिया।

उन्होंने संबंधित विभागो के अधिकारियों से कहा है कि योजना की मंशा के अनुसार कोई भी सहरिया जनजाति वर्ग का हितग्राही हितलाभ से वंचित ना रहें। कलेक्टर श्री वैद्य ने कहा कि अभी भी जिले में शत प्रतिशत हितग्राहियों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड व जाति प्रमाण पत्र तथा जनधन खाते सहित अन्य हितलाभ पूरे नहीं कराए गए है। उन्होंने संबंधित विभागो के अधिकारियों खासकर जनपदो के सीईओ को कारणो सहित समुचित जानकारियां जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है ताकि यह स्थिति स्पष्ट हो सकें कि किस ब्लाक में किस-किस योजना के कुल कितने-कितने हितग्राही हितलाभ से वंचित है और उन तक हितलाभ नहीं पहुंचने के क्या कारण है। कलेक्टर श्री वैद्य ने कहा कि पीएम जनमन योजना की मंशा के अनुसार हर घर में बिजली व नल कनेक्शन पहुंचाने के कार्य भी सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरे किए जाने है वहीं सहरिया जनजाति बसाहटो में आवागमन में सहूलियत हो इसके लिए सडको निर्माण व कम्यूनिकेशन सुगमता से हो सकें इस हेतु मोबाइल टॉवर भी स्थापित किए जाने है अतः इन कार्यो में संबंधित विभाग किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। कार्यो के संपादन में कहीं कोई दिक्कत आती है तो स्थानीय एसडीएम अथवा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाए ताकि समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सकें।

बचाव एवं राहत कार्यों के लिए नपा के अधिकारी, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने का आदेश जारी

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में जारी अनवरत वर्षा को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्र विदिशा में बाढ़ अतिवर्षा की स्थिति से निपटने एवं बचाव तथा राहत कार्यों के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी विदिशा के द्वारा आदेश जारी कर नगर पालिका में पदस्थ विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाने के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में उल्लेख है कि प्रभारी, सहायक कर्मचारी एवं दैनिक वेतन कर्मचारी, श्रमिकों के द्वारा अति वृष्टि एवं निरंतर वर्षा के समय संबंधित अधिकारी, कर्मचारी निकाय द्वारा पुराना अस्पताल परिसर स्थित स्वास्थ्य शाखा गैरिज में स्थापित नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहकर राहत एवं बचाव कार्य करेंगे। शेष समय में संबंधित कर्मचारी या श्रमिक अपना नियमित कार्य संपादित करेंगे। आपदा प्रबंधन में संलग्न समस्त अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे अपना मोबाइल चालू रखेंगे यह आदेश अवकाश दिवस में भी लागू रहेगा। जारी आदेश में उल्लेख है कि नगरीय क्षेत्र विदिशा के वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 39 तक के लिए सहायक यंत्री सुश्री वैशाली पाण्डेय मो. 9098432245 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा सहायक के लिए वार्ड क्रमांक 1 से 20 तक के लिए स्वच्छता निरीक्षक श्री राजेश शर्मा मो. 9893910144 एवं वार्ड क्रमांक 21 से 39 तक के लिए स्वच्छता निरीक्षक श्री दिनेश सिंह तोमर मो. 9826852759 को दायित्व सौंप गए हैं।

इसके अलावा विदिशा नगरीय क्षेत्र के सभी 39 वार्डों में कुल तीन दलों का गठन किया गया है। जिनमें प्रथम दल वार्ड क्रमांक 1 से 13 तक के लिए प्रभारी अधिकारी उपयंत्री श्री राम प्रकाश जायसवाल मो. 7869328941 के साथ-साथ अन्य सहयोगी कर्मचारियों व स्वास्थ्य दल में कर्मियों को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार द्वितीय दल में वार्ड क्रमांक 14 से 26 तक के लिए उपयंत्री सुश्री नीलम रजक मो. 8878712925 को प्रभारी अधिकारी तथा अन्य सहयोगी कर्मचारी व स्वास्थ्य दल में कर्मियों को गठित किया गया है तथा तृतीय दल में वार्ड क्रमांक 27 से 39 तक के लिए उपयंत्री श्री संजय श्रीवास्तव मो. 9993045359 को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के साथ-साथ अन्य सहयोगी कर्मचारियों व स्वास्थ्य दल में कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इन सभी वार्डों में संबंधित वार्डों के प्रभारी मेट एवं दरोगा वार्डो से संबंधित अधीनस्थ सफाई कर्मचारियों से आपदा राहत कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं उपस्थिति आदि रिकॉर्ड का संधारण करेंगे। नगरीय क्षेत्र विदिशा में चतुर्थी दल का गठन भी किया गया है। जो सांय 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक क्रियाशील रहेगा। इस कार्य के लिए उपयंत्री श्री संजीव जैन मो. 9806374170 को प्रभारी तथा श्री राजेश बेनवाल मो. 8878906022 एवं श्री राधेश्याम घेंघट मो. 6261036472को सहायक बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों को भी इस दल में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त पुराना जिला चिकित्सालय स्थित नगर पालिका कार्यालय बाढ़ नियंत्रण कक्ष में अन्य कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। जिसमें तीन प्रभारी अधिकारी व तीन सहायक कर्मियों को दायित्व सौंपे गए हैं। एआर ए श्री प्रदीप शर्मा मोबाइल नंबर 9827071370 एवं श्री योगेश व्यास मो. 9893731108 तथा श्री राजेश दुबे मो. 7898120 363 प्रातः 8 बजे से सांय चार बजे तक, सहायक ग्रेड 3 श्री सतीश डेहरिया मो. 9644 749 302 तथा श्री सत्यनारायण शर्मा मो. 8103053204 एवं श्री जगदीश पटेल मो. 9685 964523 सांय चार बजे से रात्रि 12 बजे तक तथा सहायक ग्रेड 3 श्री पंकज रघुवंशी मो. 7987329530 तथा श्री राम नारायण रघुवंशी 9926322510 एवं श्री राजू पाल 8120518323 रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 तक उपस्थित रहकर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

मप्र में कम होती नौकरियों पर कमलनाथ ने उठाए गंभीर सवाल, पोस्ट करके मोहन यादव सरकार को बताया इंवेटबाज

मप्र। मध्यप्रदेश में कम होती नौकरियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस दिग्गज कमलनाथ ने गंभीर सवाल उठाए हैं उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके मोहन यादव सरकार पर इंवेटबाजी करने के आरोप भी लगाए हैं कमलनाथ ने अपनी पोस्ट में कहा है कि %मध्य प्रदेश और पूरे देश में नौकरियों में कमी आ रही है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्व्क्त्ह के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023-24 में देश में सात लाख नौकरियां कम हुई है और मध्यप्रदेश में 29 हज़ार नौकरी कम हुई है कमलनाथ कहते हैं कि सवाल यह है कि %अगर सरकार न तो सार्वजनिक क्षेत्र में और न ही निजी क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध करा रही है तो आख़िर नौकरियों को लेकर उसकी नीति क्या है? कमलनाथ डिमांड करते हैं कि सरकार को नौकरियों को लेकर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

सरकार की भर्ती प्रक्रिया भी संदिग्ध- कमलनाथ

कमलनाथ लिखते हैं कि %यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ़ नौकरियां घट रही है, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और सरकारी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह संदिग्ध होती जा रही है तो दूसरी तरफ़ प्रदेश सरकार सिर्फ़ इवेंट बाजी में व्यस्त है और कपोल कल्पित वादे करने में जुटी हुई है प्रदेश का नौजवान इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा और कांग्रेस पार्टी हर कदम पर नौजवानों के साथ खड़ी है%. कमलनाथ की इस पोस्ट को लेकर सरकार ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है।

करोड़ों की लागत से बना नेशनल हाईवे पहली ही बारिश में उखड़ा, सामने आई भ्रष्टाचार की हकीकत

मध्य प्रदेश में बदहाल सड़कों की हकीकत किसी से छिपी नहीं है आए दिन मध्य प्रदेश की सड़को पर कई लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं लेकिन, इसके बाद भी न तो सड़क में सुधार होता है, और न ही सिस्टम इसे सुधारने का प्रयास करता है ताजा मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से है यहां सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी सड़क ही गड्ढों से भरी पड़ी है. लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।

एक बारिश भी नहीं झेल पाई सड़क

दरअसल सिवनी को छिंदवाड़ा से जोड़ने वाले नेशनल हाइवे नंबर 347 की तस्वीरें बदहाली बताने के लिए काफ़ी हैं सिवनी से शुरू होकर छिंदवाड़ा ज़िले के चौरई तक सड़क का यही हाल है सबसे हैरानी की बात ये है कि इस सड़क का निर्माण अभी चार महीने पहले ही किया गया है. 61 किमी लंबी इस सड़क को पूरी तरह से उखाड़कर करोड़ों रुपये की लागत से फिर से बनाया गया है लेकिन, 4 महीने में ही ये सड़क दम तोड़ती नज़र आ रही है।

गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढे?

सड़क में कई जगह गड्ढे इतने ज़्यादा है कि यात्रियों को ज़िग्ज़ैग करते हुए गुज़रना पड़ता है. बंहोड़ी गांव की पहले सड़क के बीच का हिस्सा धंस गया है इसीलिए उसके चारों ओर

बैरिकेड लगाए गए हैं हाइवे के कुछ हिस्से में मालूम ही नहीं होता कि सड़क के बीच में गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच कहीं कहीं सड़क है. हाइवे की इस दुर्दशा के लिए निर्माण करने वाली कंपनी तो ज़िम्मेदार है ही लेकिन सवाल नितिन गडकरी के मातहत काम करने वाली ह्ल्द्ध पर भी उठता है कि आख़िर 4 महीने पहले ही बने नेशनल हाइवे की ये दुर्दशा क्यों हो गई? स्थानीय लोगों की माने तो इस सड़क से बेहतर उनके लिए पुरानी सड़क थी ग्रामीणों ने कहा कि पहले ऐसे हालात नहीं थे नए सड़क निर्माण के बाद हालात बहुत खराब हो गए हैं राहगीर कहते हैं कि सरकार को शर्म करनी चाहिए कि इतने बड़े गड्ढों से होकर लोग कैसे निकलें? लोग कहते हैं इस सड़क को देखकर वाहन चलाने की हिम्मत नहीं होती है. सड़क की खस्ता हालत के कारण ही हर रोज कोई न कोई घटना सामने आती ही रहती है. स्थानीय लोगों की माने तो जब इस सड़क का निर्माण किया गया. तब इसकी गुणवत्ता को लेकर कोई ध्यान नहीं रखा गया. यही कारण है कि आज ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं।

शिवराज सिंह चौहान की मांग पर मप्र में मची हलचल

मप्र। मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर इलैया राजा टी बीते कल मंगलवार को अचानक से सुर्खियों में आ गए हैं चर्चा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इलैया राजा को निज सचिव के रूप में कृषि मंत्रालय में पदस्थ करने की मांग की है और इसके लिए केंद्रीय कार्मिक विभाग के साथ पत्राचार भी कर लिया गया है लेकिन पीएमओ की मंजूरी आना अभी शेष है.इलैया राजा टी. वर्तमान में मप्र पर्यटन विकास निगम के एमडी के रूप में पदस्थ हैं इसके पहले वे भिंड, इंदौर, रीवा और जबलपुर में कलेक्टर के रूप में पदस्थ रहे हैं इलैया राजा टी. मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं लेकिन वे एमपी कैडर के आईएएस अफसर हैं इलैया राजा की गिनती मप्र के कर्मठ और ईमानदार अफसरों में होती है अच्छी छवि की वजह से ही वे बेहद कम समय में काफी लोकप्रिय भी हुए और शिवराज सिंह चौहान के खेमे में भी जल्द शामिल हो गए थे। इलैया राजा टी. को केंद्रीय कृषि मंत्रालय में निज सचिव के रूप में पोस्टिंग देने के लिए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के साथ पत्राचार किया गया है अब पीएमओ की मंजूरी का इंतजार हो रहा है इलैया राजा ने यह तो स्वीकार किया कि उनकी दिल्ली पोस्टिंग को लेकर मंगलवार सुबह से ही सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं लेकिन अधिकृत रूप से उनके पास इसे लेकर कोई भी जानकारी नहीं है और न ही वल्लभ भवन से या केंद्रीय कार्मिक विभाग से उनके पास कोई आदेश अब तक आया है।

पिछले दिनों से हो रही बारिश के चलते तालाबों की स्थिति में हो रहा है सुधार

इन्दौर। पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश के चलते यशवंत सागर से लेकर कई तालाबों में पानी की स्थिति में न केवल सुधार आया, बल्कि कई तालाब आधे से ज्यादा भर गए हैं और आने वाले दिनों में जल्द ही लबालब होने की संभावना है, वहीं सबसे पहले छोटा सिरपुर तालाब लबालब हो गया है। नगर निगम ने विभिन्न बड़ी संस्थाओं और कंपनियों की मदद से शहर के तालाबों का गहरीकरण और वहां विभिन्न कार्य कराए थे, ताकि तालाबों की स्थिति बेहतर हो सके। करीब एक दर्जन संस्थाओं ने तालाबों के हिस्से संवारने से लेकर उनका गहरीकरण और आसपास के खाली पड़े हिस्सों में पौधारोपण किया था इनमें चेन्नई, बेंगलुरु से लेकर कई शहरों की कंपनियों ने तालाबों की गोद लेने की इच्छा भी जाहिर की थी। तालाबों की बेहतर स्थिति के कारण अब बारिश में वहां पानी आने लगा है। इसके लिए निगम की टीम ने अपने स्तर पर तालाबों की चैनलों की साफ- सफाई शुरू कराई थी, ताकि पहाडि़यों से आने वाला बारिश का पानी तालाबों तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए कई स्थानों पर लोगों द्वारा किए गए कब्जे भी हटाए गए थे। बिलावली, सिरपुर, छोटा बिलावली, पीपल्यापाला तालाबों के आसपास ड्रोन की मदद से चैनलें ढूंढी गई और वहां सफाई के साथ-साथ कब्जे भी हटाए गए थे, लेकिन कई स्थानों पर अभी भी मैरिज गार्डनों से लेकर दुकानों और मकानों के कब्जे बरकरार हैं। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक अब पिछले हफ्ते भर से हो रही लगातार बारिश के चलते तालाबों में पानी पहुंचने लगा है और कई तालाब बेहतर स्थिति में हैं तो कई आधे से ज्यादा भर चुके हैं।

इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी में चला बुलडोजर

इंदौर। इंदौर शहर के न्याय नगर की कृष्णबाग कॉलोनी में बरसते पानी में 0.72 हेक्टेयर भूमि पर बने 71 मकान हटाने पहुंचे अमले को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अमले के पहुंचने से पहले सैकड़ों महिलाएं और बच्चे गली के मुहानों पर खड़े हो गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे आंखों में आंसू लिए महिलाएं बारिश के चलते आशियाना नहीं तोड़ने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी न्यायालय का हवाला देकर कार्रवाई पर अड़े रहे। भारी मशक्कत के बाद महिलाओं को हटाकर गलियों में जेसीबी पहुंची और अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हुई। लोग बिलखते रहे, कई जेसीबी के सामने लेट गए, तो ऊपर भी चढ़ गए पुलिस ने उन्हें हटाकर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया मकान टूटते देख लोगों ने पथराव भी किया। 15 मकान तोड़ने के बाद विरोध को देखते हुए कार्रवाई को रोक दिया गया करीब 17 साल पहले लोगों ने कॉलोनी में भूखंड खरीदकर मकान बनाए। रजिस्ट्री के बाद सभी तरह के टैक्स भी दे रहे हैं खजराना ग्राम में आने वाली इस जमीन का फैसला न्यायालय ने श्रीराम बिल्डर के पक्ष में दिया है इसके बाद शुक्रवार को प्रशासन यहां अतिक्रमण हटाने पहुंचा था रहवासी अपने घरों को टूटते देख आपा खो बैठे, आंखों में आंसू लिए अधिकारियों से मिन्नतें करते रहे। मकान से सामान निकालने की मोहलत मांगते रहे भारी विरोध और मिन्नतें देखकर निर्माणाधीन मकानों को हटाने पर सहमति बनी।

स्कूली वाहनों की चेकिंग की मुहिम जारी- 3 वाहन जब्त, 5 वाहन पर जुर्माना

इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर स्कूली वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर द्वारा स्कूली वाहनों की विशेष चेकिंग की गई। इस अभियान में लापरवाही पाये जाने पर 3 स्कूली वाहनों को जब्त किया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि कलेक्टर सिंह के निर्देश पर वाहन की गति, स्पीड गवर्नर सहित दस्तावेज की चेकिंग की जा रही है। बच्चों एवं पालकों से चालक-परिचालक के व्यवहार के बारे में फीडबैक भी लिया जा रहा है। वाहनों की चेकिंग की कार्यवाही निरन्तर जारी है। निरीक्षण के दौरान क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया पाये जाने पर 3 मैजिक वाहनों को जब्त किया गया। तीनों के ही परमिट फिटनेस भी नहीं थे। बच्चों को सुरक्षित स्कूल छोड़ने के बाद वाहनों को जब्त किया गया। इन स्कूली वाहनों सहित 5 अन्य वाहनों पर भी कार्यवाही की गई जिनसे 50 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया। वाहन चालकों को अपने वाहन के दस्तावेज साथ रखने, वाहन को ठीक हालात में रखने तथा बैठक क्षमता के अनुसार ही बच्चों को बैठाने की हिदायत दी गई।

इंदौर के करीब बनेगी प्रदेश की पहली स्मार्ट इंटीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप

इंदौर। नगर निगम ने इंदौर में नर्मदा का चौथा चरण लाने की तैयारी तेज कर दी है इस योजना पर 1900 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है निगम को अमृत-2 योजना के तहत नर्मदा के चौथे चरण के लिए 1100 करोड़ रुपये मिलने हैं। शेष 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था के लिए निगम अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (ढ्ढस्नष्ट) से ऋण लेगा।इसके लिए ढ्ढस्नष्ट के अधिकारियों ने जलूद और आसपास के क्षेत्रों का दौरा भी कर लिया है। निगम नर्मदा के चौथे चरण को इंदौर लाने के साथ-साथ नर्मदा के पहले, दूसरे और तृतीय चरण की लाइनों के रखरखाव, सुधार कार्य भी करेगा यही वजह है कि इसकी लागत 1,700 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,900 करोड़ पहुंच गई है।

चौथे चरण के कार्य को पूरा करने के लिए नगर निगम ने दिसंबर 2026 तक की समय सीमा तय की है नर्मदा के चौथे चरण के इंदौर पहुंचने के बाद इंदौर को रोजाना 836 एमएलडी पानी मिलने लगेगा इस चरण की खास बात यह होगी कि इसमें पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए बनाए गए संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा नर्मदा के चौथे चरण का सेटअप पूरी तरह से अलग होगा। वर्तमान में जलूद से नर्मदा जल को जमीन से करीब आधा किमी ऊंचा पंप कर वाचू पॉइंट तक पहुंचाया जाता है इसके बाद यह गुरुत्वाकर्षण बल से इंदौर की ओर बहता है। नर्मदा के चौथे चरण में पानी को करीब 250 मीटर ऊंचा उठाकर लाया जाएगा इसके लिए नए संपवेल भी बनाया जाना हैं।

हर वार्ड की 5 बैकलाइन संवारेंगे, निगम का सम्पूर्ण बजट एक नजर में

इंदौर। शहर की साफ-सफाई बदहाली का शिकार है और केन्द्र सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण भी जल्द शुरू किया जाना है, जिसके चलते अब रोजाना महापौर और आयुक्त दौरे कर रहे हैं, तो आज के बजट में भी महापौर ने स्वच्छता की चुनौती को स्वीकार करते हुए सर्वेक्षण में लगातार आठवीं बार नम्बर वन बने रहने का दावा भी किया है महापौर का कहना है कि शहर की जनता के सहयोग, सफाई मित्रों के समर्पण, प्रशासनिक अधिकारियों और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही इंदौर लगातार सात बार नम्बर वन बना है अब वेस्ट टू एनर्जी हमारी प्राथमिकता है हम ऊर्जा का उत्पादन कर निगम की आय में बढ़ोतरी करेंगे। जिस तरह वर्तमान सीएनजी प्लांट का उल्लेख वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में किया और उसे एक आदर्श मॉडल बताया, उसी तर्ज अब कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित होगा और बैकलेन के ट्रांसफॉर्मेशन का काम प्राथमिकता से करेंगे हर वार्ड की 5 बैकलाइनों को संवारेंगे इस बजट में स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित इंदौर के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। थ्री आर नवाचार के तहत थैला बैंक, बर्तन बैंक, होम कम्पोस्टिंग, जीरो वेस्ट, ईवेंट, रीयूजेबल किट के नवाचारों के साथ ही इस साल नागरिकों के लिए बेस्ट रूफटॉफ गार्डन कॉम्पटीशन भी आयोजित की जाएगी। सभी 85 वार्डों में मौजूद बैकलेन का काम भी प्राथमिकता से किया जा रहा है और लगभग 300 बैकलेन में यह कार्य पूर्ण हो चुका है अब प्रत्येक वार्ड में 5-5 बैकलाइनों को संवारने के कार्य का लक्ष्य रखा गया है। 30 स्लम बस्तियों को ग्रीन स्लम के रूप में विकसित करेंगे 10 वार्डों को चिन्हित कर एक्यूआई प्रोटोकॉल पर आधारित परियोजनाओं, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान, 19 चौराहों को चिन्हित कर सिग्नल पर रेड लाइट होने पर वाहनों के इंजन बंद करने का अभियान भी चलेगा और आगामी दो महीने में कचरा संग्रहण के 150 नए वाहन खरीदेंगे। नागरिक सुविधाघरों के उन्नयन के साथ ही नए सुविधाघरों का निर्माण भी होगा। जीरो कार्बन क्रेडिट के लक्ष्य पर भी नगर निगम काम कर रहा है, जिसमें जलूद में सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है , जिसके लिए निगम ने ग्रीन बॉण्ड के जरिए पर्याप्त धन राशि एकत्रित भी की है। शहर की 125 ड्रैनेज लाइनों के कार्यों पर 100 करोड़ खर्च होंगे और स्मार्ट सिटी का कार्यकाल भी केन्द्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है, जिसके चलते जल प्रदाय और सीवर लाइन के प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा नमामि गंगे योजना के तहत 511 करोड़ की लागत से 120, 40 और 35 एमएलडी एसटीपी के प्लांट की मंजूरी भी हो चुकी है, तो 80 और 40 एमएलडी के एसटीपी नए प्लांट भी लगाए जाएंगे पुराने ड्रैनेज सिस्टम को सुधारने की व्यापक कार्य योजना भी बनाई है, जिसमें 320 किलोमीटर लम्बाई में सीवरेज लाइन डाली जाएगी।

इंदौर को मिलेगा भरपूर पानी, नर्मदा के चौथे चरण की तैयारी शुरू

इंदौर। नगर निगम ने इंदौर में नर्मदा का चौथा चरण लाने की तैयारी तेज कर दी है इस योजना पर 1900 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है निगम को अमृत-2 योजना के तहत नर्मदा के चौथे चरण के लिए 1100 करोड़ रुपये मिलने हैं शेष 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था के लिए निगम अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (ढ्ढस्नष्ट) से ऋण लेगा इसके लिए ढ्ढस्नष्ट के अधिकारियों ने जलूद और आसपास के क्षेत्रों का दौरा भी कर लिया है। निगम नर्मदा के चौथे चरण को इंदौर लाने के साथ-साथ नर्मदा के पहले, दूसरे और तृतीय चरण की लाइनों के रखरखाव, सुधार कार्य भी करेगा यही वजह है कि इसकी लागत 1,700 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,900 करोड़ पहुंच गई है।

दिसंबर 2026 तक पूरा होगा काम

चौथे चरण के कार्य को पूरा करने के लिए नगर निगम ने दिसंबर 2026 तक की समय सीमा तय की है नर्मदा के चौथे चरण के इंदौर पहुंचने के बाद इंदौर को रोजाना 836 एमएलडी पानी मिलने लगेगा इस चरण की खास बात यह होगी कि इसमें पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए बनाए गए संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा यानी नर्मदा के चौथे चरण का सेटअप पूरी तरह से अलग होगा वर्तमान में जलूद से नर्मदा जल को जमीन से करीब आधा किमी ऊंचा पंप कर वाचू पॉइंट तक पहुंचाया जाता है इसके बाद यह गुरुत्वाकर्षण बल से इंदौर की ओर बहता है नर्मदा के चौथे चरण में पानी को करीब 250 मीटर ऊंचा उठाकर लाया जाएगा इसके लिए नए संपवेल भी बनाया जाना हैं।

बेसमेंट में संचालित कोचिंग क्लासेस, हास्पीटल, होस्टल, लाइब्रेरी की करें सघन जांच

संभागायुक्त दीपक सिंह ने समस्त कलेक्टर्स एवं नगर निगम आयुक्त को दिये निर्देश

इन्दौर। संभागायुक्त दीपक सिंह ने संभाग के समस्त जिला कलेक्टर्स एवं नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए है कि उनके जिले में बेसमेंट में संचालित कोचिंग क्लासेस, हास्पीटल, होस्टल्स, लायब्रेरी की दल गठित कर सघन जांच की जाए। उन्होंने दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में संचालित कोचिंग क्लास में पानी भरने से हुई असामयिक मौतों की घटना के मद्देनजर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की दृष्टि से संभाग के समस्त जिलों के शहर अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्डिंग के बेसमेंट में संचालित कोचिंग क्लास, हास्पीटल, लायब्रेरी, होस्टल की सघन जांच किए जाने संबंधित निर्देश दिए है। उन्होंने पृथक-पृथक क्षेत्र हेतु एक संयुक्त जांच दल गठित किया जाकर जांच के निर्देश दिए है। उन्होंने उक्त दल में कार्यपालिक दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारी, नगर पालिका अथवा निगम के अधिकारी, अग्नि सुरक्षा तथा विद्युत सुरक्षा आदि विभागों के अधिकारी को सम्मिलित करते हुए जांच दल गठित करने के निर्देश दिए है। उक्त दल निरीक्षण पश्चात प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे कि उक्त संस्थान में विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, निवास हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी संस्थान में अनियमितता पाई जाती है तो उक्त संस्थान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उक्त संबंध में जिले एवं निगम में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति संबंधित निर्देश भी दिए है।

जन सहयोग से लिखने जा रहा है इंदौर विकास की नई इबारत

चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय का होगा जीर्णोद्धार

इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर इंदौर जिले में अस्पताल, मुक्तिधाम, स्कूल आदि जन महत्व के विभिन्न स्थानों और संस्थाओं के जीर्णोद्धार के कार्य हाथ में लिये गये है। इसी के तहत इंदौर के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय का भी जीर्णोद्धार जन सहयोग के माध्यम से किया जाएगा। जीर्णोद्धार पर लगभग साढ़े 8 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। इंदौर स्थित चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के भवन का जीर्णोद्धार एवं उसमें आवश्यक सुधार कर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के लिये कार्ययोजना तैयार की गई है। इस कार्ययोजना को अमली रूप देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कलेक्टर आशीष सिंह, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ.संजय दीक्षित, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय की अधीक्षक डॉ. प्रीति मालपानी, अपर कलेक्टर गौरव बेनल, कॉलोनी सेल प्रभारी एवं संयुक्त कलेक्टर प्रदीप सोनी, इंदौर क्रेडाई एसोसिएशन के संदीप श्रीवास्तव, अतुल झँवर, नवीन मेहता, दया कुमावत एवं अन्य पदाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी के साथ अस्पताल का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के जीर्णोद्धार, आवश्यक सुधार कार्य आदि के संबंध में चर्चा की। बताया गया कि जीर्णोद्धार पर क़रीब साढ़े 8 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे इसके लिये प्लानिंग एवं डिजाइनिंग भी तैयार कर ली गई है।

कलेक्टर सिंह की पहल पर इंदौर जिले में अस्पताल, मुक्तिधाम, स्कूल आदि जन महत्व के विभिन्न स्थानों और संस्थाओं के जीर्णोद्धार के कार्य हाथ में लिये गये है। इसके तहत कुछ माह पहले इंदौर के सामाजिक संगठनों एवं सीएसआर फण्ड की मदद से शहर के 12 मुक्ति धामों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के जीर्णोद्धार एवं विकास के कार्य प्रारंभ किये गये है। इसी तर्ज़ पर चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के जीर्णोद्धार का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर अगले 6 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। क्रेडाई इंदौर इसमें विकास कार्यों का समन्वय एवं मॉनिटरिंग का कार्य करेगी । इस पहल से इंदौर को एक नई सौग़ात मिल सकेगी।

भारत में लगातार दूसरी बार 12वीं पायदान पर आया, कभी शीर्ष पर हुआ करता था इंदौर एयरपोर्ट

इंदौर। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय विमानतल जिम्मेदारों की लापरवाही का नतीजा भुगत रहा है यात्री सुविधाओं के मामले में कभी एशिया में अपनी कैटेगरी के एयरपोर्ट्स में नंबर 1 पर रहने वाला एयरपोर्ट अब 90वीं पायदान पर पहुंच चुका है। तीन माह में ही एयरपोर्ट की एशिया में रैंक 10 पायदान गिर गई है वहीं भारत के 15 एयरपोर्ट में भी टॉप पर रहने वाला इंदौर लगातार दूसरी बार 12वें स्थान पर आया है।यह खुलासा कल शाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा यात्री सुविधाओं के मामले में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा की गई एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वे की त्रैमासिक रिपोर्ट में हुआ है। एसीआई उन एयरपोर्ट पर सर्वे करती है, जहां सालाना यात्री संख्या 18 लाख से ज्यादा है। इस सर्वे में देश के एयरपोर्ट अथॉरिटी के 15 एयरपोर्ट शामिल होते हैं। वहीं भारत को मिलाकर एशिया पैसिफिक के 18 देशों से 98 एयरपोर्ट पर यह सर्वे होता है। इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक साल की दूसरी तिमाही, यानी 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 के बीच हुए सर्वे में इंदौर को देश के 15 एयरपोर्ट में से 12वां और एशिया के 98 एयरपोर्ट में से 90 वां स्थान मिला है, जबकि पिछली तिमाही, यानी जनवरी से मार्च के बीच इंदौर भारत में तो 12वें स्थान पर ही था, लेकिन एशिया में 80वें स्थान पर था। इस तरह

एशिया के एयरपोर्ट में भारत की रैंकिंग में 10 पायदानों की कमी आई है। सर्वे में एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों से एयरपोर्ट पर उपलब्ध सुविधाओं को 31 बिंदुओं में बांटकर अंक देने के लिए कहा जाता है। सबसे अच्छे के लिए 5 और सबसे बुरे के लिए 1 अंक देना होता है। ताजा सर्वे में इंदौर को कुल पांच में से 4.66 अंक मिले हैं, जबकि पिछली तिमाही में इंदौर को 4.74 अंक मिले थे। इस तरह एयरपोर्ट पर यात्रियों ने सुविधाओं के मामले में पिछली बार की अपेक्षा 0.08 अंक कम दिए हैं। यात्रियों द्वारा सर्वे में इंदौर एयरपोर्ट को सबसे कम अंक अन्य उड़ानों से कनेक्शन में आसानी के बिंदु पर दिए गए हैं। पिछली तिमाही में जहां यात्रियों ने इसके लिए 4.27 अंक दिए थे, वहीं इस तिमाही में इसके लिए सिर्फ 4 अंक दिए हैं। इस तरह इस बिंदु पर एयरपोर्ट के 0.27 अंक कम हुए हैं। वहीं मनोरंजन और विश्राम सुविधाओं के मामले में भी यात्रियों ने एयरपोर्ट को पिछली बार की तुलना में कम अंक दिए हैं। शेष बिंदुओं पर एयरपोर्ट को पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा अंक मिले हैं। रिपोर्ट एक मामले में सवालों के घेरे में भी है। एयरपोर्ट पर सभी शॉपिंग काउंटर्स 23 मई से बंद हो चुके हैं। इसके बाद भी दुकानों और दुकानों का पैसा वसूल होना जैसे दो बिंदुओं पर यात्रियों ने एयरपोर्ट को क्रमश- 4.77 और 4.69 अंक दिए हैं, जो पिछली बार की अपेक्षा 0.02 और 0.06 अंक ज्यादा हैं, जबकि आशंका जताई जा रही थी कि इस मामले में एयरपोर्ट के अंक सबसे ज्यादा घटेंगे, क्योंकि यात्री शॉपिंग सुविधा न मिल पाने के कारण काफी नाराज हैं।

आरएसएस के जनता से जुड़े मुद्दों पर होगा गहन मंथन, बौद्धिक विभाग की प्रांतीय बैठक 3-4 अगस्त को

इंदौर। इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी बैठक 1 से 4 अगस्त तक होने जा रही है संघ और जनता के बीच संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी संपर्क विभाग की इस राष्ट्रीय बैठक में विभाग के 200 शीर्ष पदाधिकारी चार दिन तक अलग-अलग मुद्दों पर गहन मंथन करेंगे। बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबोले और राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख रामलाल पूरे समय मौजूद रहेंगे। बैठक में संघ के 11 क्षेत्र और सभी प्रांत के संपर्क और सहसंपर्क प्रमुख के साथ ही राष्ट्रीय सहसंपर्क प्रमुख सुनील देशपांडे और रमेश पप्पाजी भी मौजूद रहेंगे साल में एक बार होने वाली इस बैठक में करीब 25 सत्र होंगे, जिनमें संघ के अलग-अलग प्रांत और क्षेत्र के संपर्क और सहसंपर्क प्रमुख अपने साल भर के कामकाज का ब्योरा तो देंगे ही, साथ जनता के बीच लगातार मूवमेंट के दौरान संघ को लेकर जो फीडबैक मिलता है, वह भी वरिष्ठ नेतृत्व के सामने रखेंगे। इसी के आधार पर संपर्क विभाग के आगे के कामकाज को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। कई सत्र ऐसे से भी होंगे, जिसमें प्रतिनिधि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे यह बैठक में एमआर10 स्थित एचआर ग्रीन रिसोर्ट परिसर में आयोजित की गई है। इसमें पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला 31 जुलाई को ही शुरू हो जाएगा। संघ का संपर्क विभाग संघ और जनता के बीच संवाद की सबसे बड़ी कड़ी है। दशहरे पर नागपुर में होने वाले संघ प्रमुख के उद्बोधन के बाद इस उद्बोधन में शामिल मुद्दों पर संपर्क विभागीय समाज के अलग-अलग वर्ग के प्रतिनिधियों को एक फोरम पर लाकर संवाद करता है और उनकी राय संघ के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाई जाती है।

भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रह चुके हैं रामलाल

अभी संघ में राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख की भूमिका निभा रहे रामलाल वरिष्ठ प्रचारक हैं और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रह चुके हैं। इस दौर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भाजपा से संघ में वापसी के बाद उन्हें संपर्क विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंप गई।

संघ के बौद्धिक विभाग की प्रांतीय बैठक भी तीन और चार अगस्त को इंदौर में आयोजित की जा रही है इस बैठक में प्रांतीय टीम के करीब 200 पदाधिकारी शामिल होंगे इसमें संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख सुनील भाई मेहता मौजूद रहेंगे। इनके अलावा प्रांत की बौद्धिक टीम के प्रमुख पदाधिकारी सुनील बागुल, आशीष जादम, मनीष नीम बौद्धिक टीम के पदाधिकारी का मार्गदर्शन करेंगे। संघ की विचारधारा और उद्देश्य को आम लोगों तक पहुंचाने में इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

देश के सबसे स्वच्छ शहर में अब कचरे से बनेगी बिजली, 200 करोड़ रुपये की लागत से लगाया जाएगा प्लांट

इंदौर। देश के सबसे स्वच्छ शहर यानी इंदौर में कचरे से बिजली बनाने के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से कचरे से ऊर्जा बनाने का प्लांट लगाया जाएगा महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पेश किए गए साल 2024-25 के इंदौर नगर निगम के बजट में इस आशय का प्रावधान किया है महापौर भार्गव ने कहा, कचरे को ऊर्जा में बदलने की प्राथमिकता के तौर पर हम करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से नया प्लांट लगाने की योजना बना रहे हैं. यह प्लांट पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्लांट न केवल रोजाना 500 टन कचरे का निपटान करेगा, बल्कि इससे छह मेगावाट बिजली भी पैदा होगी।

इंदौर के महापौर ने आईएमसी का बजट पेश किया, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में 8 हजार 232.26 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ तमाम स्रोतों से 8 हजार 302.26 करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान है. वायु और ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए इंदौर में 19 ट्रैफिक सिग्नल चिन्हित किए गए हैं, जहां चालकों से अनुरोध किया जाएगा कि वे लाल बत्ती के हरे होने तक अपने वाहनों के इंजन बंद रखें. बजट में 150 प्रमुख चौराहों पर मुफ्त वाई-फाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है।

आज भी रहेगा बादलों और रिमझिम वाला मौसम

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में रविवार को हुई ढाई इंच बारिश के बाद फुहारों और रिमझिम वाला मौसम रहा। दिनभर में सिर्फ 6 मिमी ही बारिश हुई। अभी तक सीजन की 14 इंच बारिश हो चुकी है जबकि जुलाई में 10 इंच बारिश हो चुकी है। जुलाई का कोटा पूरा करने के लिए ढाई इंच बारिश की जरूरत है जबकि एक दिन बाकी है। मौसम विभाग ने आज रिमझिम और हल्की बारिश के आसार जताए हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में अच्छी बारिश के आसार हैं।रविवार को दिन का तापमान 24.8 (-4) डिग्री और रात का तापमान 23.6 (+1) डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इस दौरान ढाई इंच बारिश रिकॉर्ड की गई थी। सोमवार को भी मौसम में ठण्डक रही। दिन का तापमान 25.9 (-2) डिग्री और रात का तापमान 22.4 (0) डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यानी रविवार को दिन और रात के तापान में 1 डिग्री का अंतर था। सोमवार को 3 डिग्री का अंतर रहा जबकि बारिश 6 मिमी रिकॉर्ड की गई। इस बार जुलाई के आखिरी हफ्ते में हुई बारिश से उम्मीद जरूर बंधी है लेकिन अब माह का कोटा पूरा होना मुश्किल लग रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से आया सिस्टम गुजरात की ओर चला गया है। ऐसे में बुधवार से तेज बारिश का अनुमान है। अब बारिश के मौसम के करीब दो माह बाकी हैं।

संपादकीय | सत्ता पक्ष के खिलाफ ममता का कदम और संघीय मर्यादा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कब, किस मामले में क्या कदम उठा लेंगी, कई बार समझना मुश्किल होता है। नीति आयोग की बैठक में शिरकत करने का उनका रवैया भी कुछ वैसा ही था। जब विपक्षी धड़े के मुख्यमंत्रियों ने उस बैठक के बहिष्कार का आह्वान किया, तब ममता बनर्जी ने संघीय तकाजे को ऊपर रखते हुए उसमें जाने की घोषणा कर दी। वे उस बैठक में गईं, मगर चलती बैठक से तमतमा कर बाहर निकल आईं। उनका कहना था कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को बीस मिनट बोलने का समय दिया गया, अन्य मुख्यमंत्रियों को भी दस मिनट से अधिक बोलने दिया गया, मगर उन्हें पांच मिनट बाद ही बोलने से रोक दिया गया। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के लिए वित्तीय आबंटन की मांग उठाने पर उनका माइक बंद कर दिया गया। इसे लेकर सत्तापक्ष उन पर हमलावर है। वित्तमंत्री ने सफाई दी है कि हर किसी के लिए समय निर्धारित था और उसी के हिसाब से उन्हें बोलने का मौका दिया गया; ममता बनर्जी का यह आरोप सरासर गलत है कि उनका माइक बंद कर दिया गया। जाहिर है, ममता बनर्जी इसे राज्य का अपमान बताते हुए अपने पक्ष में जनमत जुटाने का प्रयास करेंगी, पर खुद विपक्षी धड़ा इसे कितनी गंभीरता से लेगा, यह देखने की बात है।ममता बनर्जी का केंद्र सरकार के साथ टकराव किसी से छिपा नहीं है और न यह पहला मौका था जब वे किसी बैठक या सभा के बीच से उठ कर बाहर निकल आईं। मगर कई लोगों का यह सवाल बना हुआ है कि आखिर नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का फैसला उन्होंने किस मकसद से किया। क्या वे इस मौके का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के लिए वित्तीय आबंटन की मांग उठाने के लिए करना चाहती थीं, या सचमुच नीतियों के निर्माण में संघीय उत्तरदायित्व पूरा करने के नेक इरादे से गईं। अगर सचमुच उन्हें संघीय मर्यादा की परवाह थी, तो इस तरह वे बीच बैठक से नाराज होकर निकली क्यों? फिर यह ढिंढोरा क्यों कि वे विपक्ष की तरफ से अकेले बैठक में शामिल हुईं। अगर उन्हें विपक्ष की परवाह होती, तो वे उसकी बहिष्कार की अपील को इस तरह ठुकरातीं नहीं। उनके बैठक में जाने के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि विपक्ष में टूट शुरू हो चुकी है। पहले ही उनके अनिश्चित रुख की वजह से विपक्ष की लड़ाई कमजोर हुई है और गठबंधन को कई बार असहज स्थितियों का सामना करना पड़ा है। जब विपक्षी गठबंधन बना था तब ममता बनर्जी ने बड़े जोशो-खरोश के साथ उसमें भागीदारी की थी, फिर वे कांग्रेस की आलोचना करने लगीं। आम चुनाव से पहले जब सीटों की साझेदारी को लेकर बातचीत चलनी शुरू हुई, तो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उनके ऐसे अनिश्चित व्यवहार से विपक्षी गठबंधन खुद आश्वस्त नहीं रहता कि वे उसमें शामिल रहेंगी भी या किसी मोड़ पर साथ छोड़ जाएंगी। निश्चित रूप से उनके इस बदलते मिजाज का असर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ता होगा। जब संसद में उनके सांसद बजट पर चर्चा करते हुए पश्चिम बंगाल की अनदेखी पर तीखा तेवर दिखा चुके थे, तो उन्हें नीति आयोग की बैठक में शामिल होने की सदाशयता दिखाने की जरूरत नहीं थी। कोई भी गठबंधन आपसी सहमति और विश्वास पर टिक पाता है। ममता बनर्जी के अस्थिर फैसलों से आखिरकार विपक्षी एकता पर असर पड़ता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकर्स की क्षमता संवर्धन के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित

इंदौर। भारतीय रिजर्व बैंक के भोपाल कार्यालय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्तपोषण में कार्यरत बैंकर्स की क्षमता संवर्धन के लिए राष्ट्रीय मिशन 3.0 (ह्रस्ह्रक्र 3.0) के अंतर्गत 29-30 जुलाई को इंदौर में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक हेमन्त कुमार सोनी ने प्रतिभागियों को समग्र आर्थिक वातावरण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्ता एवं इस क्षेत्र के विकास में बैंकों की भूमिका के संबंध में जानकारी दी।

कार्यशाला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं एच.डी.एफ.सी बैंक के उच्च अधिकारियों ने भी अपने अमूल्य अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में इंदौर क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन, वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक महाप्रबंधक श्रीमती रोशिनी हजेला ने किया। श्रीमती हजेला द्वारा भारतीय सन्दर्भ में एमएसएमई का महत्व एवं एमएसएमई वित्तपोषण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर प्रतिभागियों को विस्तार से जानकारी दी गई।

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रबंधक नवीन कुमार सिंह द्वारा एमएसएमई वित्तपोषण के तकनीकी हस्तक्षेप, अकाउंट एग्रीगेटर, ञ्जक्रद्गष्ठस् की भूमिका पर सत्र लिया गया। प्रबंधक सरवन एस द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिकार प्राप्त समिति के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त कार्यशाला में एमएसएमई क्षेत्र के लिए भारत सरकार की पहल, एमएसएमई खातों में प्रगति की निगरानी और तनाव का प्रबंधन, सीजीटीएमएसई और एनसीजीटीसी की भूमिका, एमएसएमईएस में क्रेडिट फ्लो को पुनर्जीवित करना, एमएसएमई ऋण में सीआईसी की भूमिका, ऋण दस्तावेज और एमएसएमई ऋण की वसूली के पहलुओं, सीजीटीएमएसई और एनसीजीटीसी की भूमिका, एनपीए प्रबंधन आदि विषयों के संबंध में चर्चा की गई। कार्यशाला के आयोजन में सहायक प्रबंधक श्री असीम कुमार सक्सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों ने स्स्रूश्व क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रूप से बातचीत की। प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए बताया की कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान का फायदा इंदौर क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिलेगा, जिससे रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी।

आज का कार्टून

मुलायम के लोहियावादी बोझ के बिना आधुनिक सोच रखते हैं अखिलेश

> अखिलेश जल्दबाजी करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। 5 बार के लोकसभा सांसद, 38 साल की उम्र में सी.एम. और 45 साल की उम्र में पार्टी प्रमुख बने। वे सावधानी से अपना राजनीतिक रास्ता तय कर रहे हैं। वे अपनी राजनीतिक पहचान पर कायम हैं। हालांकि कांग्रेसियों ने गांधी टोपी छोड़ दी है, लेकिन अखिलेश लाल टोपी में हर राजनीतिक कार्यक्रम में अलग दिखते हैं। वे कोई कॉमरेड नहीं हैं, लेकिन दिल से समाजवादी हैं और उनका दिमाग उदार है। शांत और मृदुभाषी, अखिलेश ने योगी और मोदी सहित किसी भी भाजपा नेता के खिलाफ एक भी जहरीला शब्द नहीं बोला है। यू.पी. भले ही एक ध्रुवीकृत युद्ध का मैदान हो, लेकिन सी.एम. के रूप में योगी और विपक्ष के नेता के रूप में अखिलेश सभ्य राजनीतिक आचरण का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए राज्य पहले आता है। दोनों एक ही आयु वर्ग के हैं और लंबे समय में संभावित पी.एम. उम्मीदवार हैं।

प्रभु चावला

एक समय की बात है, भारत में उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव नाम के एक महान पहलवान रहते थे। वे चक्र दाव में माहिर थे, यानी प्रतिद्वंद्वी को पटखनी देने की कला। उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाकर उत्तर प्रदेश के विश्वासघाती राजनीतिक अखाड़े में बड़ी कुश्ती जीती और बाद में कई राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतियोगिताओं में रैफरी की भूमिका निभाई। उनके बेटे अखिलेश यादव ने स्टारडम का राज समझ लिया है। युवा सांसद अखिलेश अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए दोस्त बना रहे हैं और दुश्मनों को त्याग रहे हैं। अखिलेश सिर्फ एक सांसद नहीं हैं वे एक मुख्यमंत्री थे। जंतर-मंतर पर एन.डी.ए. के खिलाफ क्षेत्रीय दलों द्वारा आयोजित धरने पर बैठकर अखिलेश ने यह बात साबित कर दी कि क्षेत्रीय ही राष्ट्रीय है।

उन्हें आंध्र प्रदेश के अपदस्थ मुख्यमंत्री जगन मोहन रैड्डी ने आमंत्रित किया था, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि उनकी वाई.एस.आर. कांग्रेस के पास संसद में 15 सांसद हैं और एन.डी.ए. सरकार, जिसमें उनके प्रतिद्वंद्वी चंद्रबाबू नायडू भागीदार के रूप में शामिल हैं, को उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह और अखिलेश शायद ही कभी सामाजिक या राजनीतिक कारणों से मिले हों। फिर भी, यादव जूनियर ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। यह चतुराईपूर्ण दृष्टिकोण है। अखिलेश उत्तर भारत से आगे अपने राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं और 2029 तक सपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। एक युवा नेता अखिलेश जाति कार्ड नहीं खेलते हुए खुद को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं और मुलायम के लोहियावादी बोझ के बिना आधुनिक सोच रखते हैं। सपा के लिए, यादववाद मर चुका है। अखिलेश अब एक छोटे से यादववादी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं।

जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटों के साथ सपा को शानदार जीत दिलाई और 18वीं लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, तब से वे अपनी पार्टी के अंदर और बाहर बहुत सक्रिय हैं। अब वे एक शांत स्वभाव वाले योद्धा नहीं रह गए हैं; वे व्यंग्य, कविता और शांत विचारधारा से भरपूर शोधपूर्ण भाषण देते हैं। वे विभिन्न दलों के नेताओं से मिल रहे हैं और अपने घर या संसद के बाहर प्रतीक्षा कर रहे पत्रकारों को साक्षात्कार देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।

राजनीतिक शैली में यह बड़ा बदलाव है। पिछले एक दशक से अखिलेश ने खुद को लखनऊ तक सीमित रखा और ज्यादातर करीबी लोगों से ही मिले, घर से सिर्फ पार्टी मीटिंग के लिए निकले। बाकी समय उन्होंने परिवार के साथ बिताया, घर के पिछवाड़े में फुटबॉल या क्रिकेट खेला। अब कई सालों के बाद भारत में एक नया युवा क्षेत्रीय राजा दिख रहा है जो राष्ट्रीय भूमिका निभाने के लिए बेताब है। ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन और तेजस्वी यादव मोटे तौर पर अपने गृह राज्यों में ही रहे हैं, जबकि अखिलेश दिल्ली में अपने सांसदों से घुलमिल गए हैं। उन्होंने गठबंधन बनाने और तोडने़ की कोशिश की है। उन्होंने कांग्रेस और बसपा के साथ भी हाथ मिलाया, लेकिन असफल रहे। लेकिन वे लड़ाई नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उम्र उनके पक्ष में है। अखिलेश का लक्ष्य सपा को एक समावेशी मंच में बदलना और शीर्ष पर पहुंचाना है।

उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक शैली में बदलाव किया और दागी छवि वाले पुराने विश्वासघातियों को हटाकर अपना खुद का संस्करण गढ़ रहे हैं। मुलायम की जीत का टिकट उनका कांग्रेस विरोधी एजैंडा था। 2014 में, उन्होंने मतदान के दिन से ठीक पहले रातों-रात सपा के वोट कांग्रेस को हस्तांतरित करके अमेठी में राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित की। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के विश्वास मत हारने के बाद सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए भी वे ही जिम्मेदार थे। उन्होंने राष्ट्रपति को अपनी पार्टी के 39 सांसदों के समर्थन का पत्र देने से इंकार कर दिया। फिर भी, कुछ साल बाद, वे प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति पद के लिए उनका समर्थन मांगने के लिए 10 जनपथ गए।

अखिलेश आखिरकार अपने पिता की जगह लेने जा रहे हैं। हालांकि, दोनों में एक बड़ा अंतर है। उनकी पहली लड़ाई परिवार के सदस्यों के खिलाफ थी। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें 2012 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यू.पी. सपा प्रमुख नियुक्त किया था। अखिलेश की राज्यव्यापी रथ और साइकिल यात्राओं ने उन्हें यू.पी. का पहला युवा आइकन बना दिया, जिससे सपा को दो-तिहाई से अधिक सीटें मिलीं। जैसे ही अखिलेश ने खुद को सी.एम. के रूप में स्थापित करना शुरू किया, उन्हें परिवार के भीतर विद्रोह का सामना करना पड़ा। उन्होंने मुलायम के पारिवारिक, राजनीतिक और नौकरशाही के उम्मीदवारों को बर्खास्त कर दिया। गुस्से में मुलायम ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। बेटे ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पिता को अध्यक्ष पद से हटा दिया और खुद पार्टी की कमान संभाली। यह झगड़ा चुनाव आयोग तक गया, जिसने पार्टी और उसका चिन्ह अखिलेश को दे दिया। 2017 तक, अखिलेश पूरी तरह से प्रभारी थे।

अखिलेश के इर्द-गिर्द कोई यादव नहीं है। हालांकि यादवों ने 5 चुनाव जीते हैं। उन्होंने यादवों के नेतृत्व वाली पार्टी को यादवों से मुक्त कर दिया है। हालांकि पार्टी के आधे पद और विधायक सीटें यादवों ने हथिया लीं, लेकिन अखिलेश ने अपने परिवार को आश्वस्त किया कि अगर उन्हें कभी भारत पर शासन करना है तो उन्हें अन्य समुदायों के साथ सत्ता सांझा करनी होगी। अखिलेश ने अपने पिता के मुस्लिम और यादव के राजनीतिक गठबंधन को कमजोर कर दिया और एक नया पी.डी.ए.(पिछड़े या पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यक) नारा गढ़ा। पी.डी.ए. एक गेम-चेंजर था इसने 2024 में सपा को 5 सांसदों से 37 पर पहुंचा दिया। उम्मीदवारों की सूची में गैर-यादव बहुमत में थे। जैसा कि सी.एम. के रूप में उनके ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है, अखिलेश ने आधुनिकतावादी की भाषा बोलनी सीख ली है।

फिर भी, अखिलेश जल्दबाजी करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। 5 बार के लोकसभा सांसद, 38 साल की उम्र में सी.एम. और 45 साल की उम्र में पार्टी प्रमुख बने। वे सावधानी से अपना राजनीतिक रास्ता तय कर रहे हैं। वे अपनी राजनीतिक पहचान पर कायम हैं। हालांकि कांग्रेसियों ने गांधी टोपी छोड़ दी है, लेकिन अखिलेश लाल टोपी में हर राजनीतिक कार्यक्रम में अलग दिखते हैं। वे कोई कॉमरेड नहीं हैं, लेकिन दिल से समाजवादी हैं और उनका दिमाग उदार है। शांत और मृदुभाषी, अखिलेश ने योगी और मोदी सहित किसी भी भाजपा नेता के खिलाफ एक भी जहरीला शब्द नहीं बोला है। यू.पी. भले ही एक ध्रुवीकृत युद्ध का मैदान हो, लेकिन सी.एम. के रूप में योगी और विपक्ष के नेता के रूप में अखिलेश सभ्य राजनीतिक आचरण का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए राज्य पहले आता है। दोनों एक ही आयु वर्ग के हैं और लंबे समय में संभावित पी.एम. उम्मीदवार हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है कि दो 'यू.पी. के लड़कों' (राहुल और अखिलेश) में से कौन कप जीतेगा? 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आंशिक जवाब देंगे। मुलायम का सबक रहा है, 'अगर आप टूर्नामैंट जीतते हैं तो मैच हारना ठीक है'। इस मामले में, अखिलेश दोस्तों और दुश्मनों दोनों के खिलाफ खेल रहे हैं। राजनीति में कुछ स्थायी दुश्मन और दोस्त होते हैं, लेकिन स्थायी हितों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

प्रेमचंद जयंती 31 जुलाई के अवसर पर

प्रेमचंद ने कहा था - साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है

हरनाम सिंह

अब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना था। हम साहित्य को केवल विलासिता की वस्तु नहीं समझते हैं। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो। जो हम में गति संघर्ष और बेचैनी पैदा करे सुलाए नहीं।

युग पुरुष महान लेखक प्रेमचंद ने यह साहित्य की कसौटी दी है। वर्तमान में लेखक इस पर कितने खरे उतर रहे हैं, वे इसी आधार पर आत्म अवलोकन कर सकते हैं। प्रेमचंद के अनुसार साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं हैं लेकिन सर्वोत्तम परिभाषा है ÷जीवन की आलोचना÷ चाहे वह निबंध के रूप में हो अथवा कहानी या काव्य में हो। प्रेमचंद कहते हैं कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें सौंदर्य की अनुभूति न हो। काव्य और साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाना है। मनुष्य का जीवन केवल स्त्री-पुरुष प्रेम का जीवन नहीं है। साहित्य का विषय श्रृंगारिक मनोभाव और उससे उत्पन्न होने वाली विरह व्यथा, निराशा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। साहित्य केवल नायक- नायिका के संयोग-वियोग की कहानी नहीं सुनाता है। अब वह जीवन की समस्याओं पर विचार करता है।

पुराने जमाने में समाज की लगाम मजहब के हाथ में थी। वह भय और प्रलोभन से काम लेता था। पुण्य और पाप उसके साधन थे। अब साहित्य ने यह काम अपने जिम्में ले लिया है। उसका साधन सौंदर्य और प्रेम है। बंधुत्व और समता, सभ्यता तथा प्रेम सामाजिक जीवन के प्रारंभ से ही आदर्शवादियों का स्वप्न रहा है। धर्म प्रवर्तकों ने इस स्वप्न को सच्चाई में तब्दील करने के सतत प्रयास किये किंतु वे निष्फल रहे। सभी पीर पैगंबरों, धर्म प्रवर्तकों ने नैतिकता की नींव पर समता की इमारत खड़ी करनी चाही पर उन्हें सफलता नहीं मिली। आज छोटे- बड़े का भेद निष्ठुर रूप से प्रकट हो रहा है। जो दलित है, पीड़ित हैं, वंचित है चाहे वह व्यक्ति हो या समूह उसकी हिमायत और वकालत करना साहित्य का फर्ज है। साहित्यकार या कलमकार स्वभावत÷ प्रगतिशील होता है। अगर यह उसका स्वभाव न होता तो शायद वह साहित्यकार ही नहीं होता।

साहित्य अपने काल का प्रतिबिम्ब होता है। उसके लिए भाषा साधन है साध्य नहीं। साहित्य का लक्ष्य केवल महफ़िल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना न गिराइए। वह देश भक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है।

(1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले लखनऊ अधिवेशन में प्रेमचंद द्वारा दिए गए उद्घाटन भाषण से)

संक्षिप्त समाचार

बीए-बीकॉम और बीएससी के रिजल्ट 10 अगस्त तक आएंगे

इंदौर। ग्रेजुएशन सेकंड ईयर की परीक्षाएं देवी अहिल्या विश्विवद्यालय ने जुलाई पहले सप्ताह में संपन्न करवाई हैं विद्यार्थियों की आंसर शीट की जांच करवाई जा रही है। पहले बीबीए फॉरेन ट्रेड, होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेन-बीसीए जैसे छोटे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन पूरा हुआ। क्योंकि इनमें विद्यार्थियों की संख्या दो से चार हजार के बीच है।विश्वविद्यालय ने 26 जुलाई को बीबीए-बीसीए सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट निकाला। करीब 70 फीसद छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हुए है। 1200 विद्यार्थी अलग-अलग विषय में फेल हो गए। संबंधित विषयों में रिव्यू के लिए विश्वविद्यालय ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी।25 हजार से अधिक विद्यार्थी

अधिकारियों के मुताबिक बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे बड़े पाठ्यक्रमों के रिजल्ट आने में दस दिनों के भीतर घोषित किया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम में 25 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) वाले पाठ्यक्रम होने से 40-50 विषयों की कॉपियां जांचना पड़ती है।इसमें 40-50 दिन का समय लगता है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी का कहना है कि कॉलेजों से प्राप्त स्नातक सेकंड ईयर के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा के अंक मिल गए है। इन दिनों सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जा रहा है। कॉपियां जांचने के लिए मूल्यांकन केंद्र को 5 अगस्त तक का समय दिया है।

चौबीस घंटे के भीतर विश्वविद्यालय ने बीएड पहले और तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट निकाला है 40-44 प्रतिशत के बीच विद्यार्थी पास हुए है। शेष विद्यार्थियों को एक-एक विषय में एटीकेटी आई है पांच फीसद विद्यार्थी फेल हो चुके है। मगर रिजल्ट को लेकर विद्यार्थियों ने आपत्ति उठाई है उन्होने मूल्यांकन कार्य ठीक से नहीं करने का आरोप लगाया है अधिकांश विद्यार्थियों ने तीन व चार नंबर से रोकने की बात कहीं विश्वविद्यालय ने रिव्यू के लिए लिंक खोल दी है। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को कॉपियां देखने की सलाह दी है। उसके बाद मूल्यांकन में गड़बड़ी पर चर्चा करने की बात कहीं।

विश्वविद्यालय का 50 साल का डाटा होगा डिजिटलाइज्ड कार्य परिषद ने दी मंजूरी, टेंडर होगा जारी

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपना पचास साल का डाटा डिजिटलाइज्ड करने जा रहा है कार्यपरिषद से मंजूरी मिलने के बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही टेंडर निकालेगा इसके बाद एजेंसी की तलाश शुरू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1970 से 2020 के बीच पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अंकसूची-डिग्री और अन्य दस्तावेज को डिजिटल प्रारूप में बदलने की तैयारी में लगा है इन पचास सालों में विश्वविद्यालय से लाखों छात्र-छात्राएं पढ़कर निकल चुके है। अधिकारियों के मुताबिक डाटा डिजिटलाइज्ड करने के पीछे यह उद्देश्य है कि कितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई पूरी की है और कितने छात्र-छात्राएं फेल व पढ़ाई छोड़ चुके हैं 2018 से पुराना डाटा डिजिटल करने में जुटा 2018 से विश्वविद्यालय अपना पुराना डाटा डिजिटल करने की कवायद करने में लगा है। इसके लिए राजभवन ने प्रदेशभर की विश्वविद्यालय की समिति बनाई थी। कई साफ्टवेयर कंपनी ने प्रेजेंटेशन भी दिया था। 2020 में प्रक्रिया धीमी हो गई। बाद में उच्च शिक्षा विभाग ने एनईपी से विद्यार्थियों का डाटा डिजिटल करने के निर्देश दिए है। 2023-24 में विश्वविद्यालय ने स्नातक अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले 80 हजार विद्यार्थियों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन कर दी है। अब 1970 से 2020 में पढ़कर निकल चुके विद्यार्थियों का डाटा डिजिटल करने पर विचार-विमर्श किया गया है, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, एमए, एमकॉम, एमएससी सहित अन्य कोर्स शामिल हैं विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का अलग-अलग डाटा रखने पर जोर दिया है। बीती 26 जुलाई को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने डाटा डिजिटल करने की मंजूरी दी है। अब विश्वविद्यालय अगस्त में टेंडर जारी कर सकता है। इसके बाद आइटी कंपनियों का प्रेजेंटेशन भी रखा जाएगा।

मिनिमम बैलेंस पेनल्टी पर सरकारी बैकों ने काटी आपकी जेब, पांच साल में कमा लिए 8,500 करोड़

नईदिल्ली, एजेंसी। अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होने पर बैंक ग्राहकों से जुर्माना वसूलते हैं। देश के सरकारी बैंकों ने पिछले पांच साल में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से 8,500 करोड़ रुपये कमाए। हालांकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से ही मिनिमम बैलेंस पेनल्टी वसूलना बंद कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद पिछले पांच साल में सरकारी बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की राशि 38 फीसदी बढ़ गई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है।

इसके मुताबिक सरकारी बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2024 के दौरान मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के रूप में 8,500 करोड़ रुपये कलेक्ट किए। जानकारी के मुताबिक 11 सरकारी बैंकों में से छह ने मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं होने पर वसूली की जबकि चार बैंकों में मिनिमम एवरेज मंथली बैलेस नहीं होने पर ग्राहकों पर जुर्माना लगाया। ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट शहरों और गांवों में अलग-अलग है। उदाहरण के लिए पंजाब नेशनल बैंक के शहरी ग्राहकों के लिए सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम तिमाही औसत बैलेंस 2,000 रुपये है। कस्बों के लिए यह 1,000 रुपये और गांवों के लिए 500 रुपये है। मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर शहरों में 250 रुपये, कस्बों में 150 रुपये और गांवों में 100 रुपये तक काटे जा सकते हैं।

चौधरी ने कहा कि बैंकों को अकाउंट्स खोलते समय ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस के बारे में बताना चाहिए। अगर ग्राहक मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करता है तो बैंकों को जुर्माने के बारे में ग्राहक को बताना चाहिए। एसबीआई ने 2019-20 में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से 640 करोड़ रुपये कमाए थे। लेकिन उसके बाद बैंक ने यह प्रैक्टिस बंद कर दी। 2023-24 में पंजाब नेशनल बैंक ने इस पेनल्टी से 633 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 387 करोड़ रुपये, इंडियन बैंक ने 369 करोड़ रुपये, केनरा बैंक ने 284 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ इंडिया ने 194 करोड़ रुपये कमाए।

75 पर जा सकता है एनर्जी का शेयर

नईदिल्ली, एजेंसी। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर में आज मंगलवार को भी 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया। कंपनी के शेयर आज 68.25 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए। यह इसका 52 वीक का नया हाई प्राइस भी है। बता दें कि यह सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर में बढ़त का लगातार सातवां दिन है। शेयरों में इस तेजी के पीछे जून तिमाही के नतीजे हैं। दरअसल, पवन टरबाइन निर्माता द्वारा जून तिमाही की आय घोषित करने के बाद से छह कारोबारी 7 कारोबारी सेशंस में यह स्टॉक 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। सुजलॉन ने 22 जुलाई को बाजार बंद होने के बाद अपने जून तिमाही के नतीजों की घोषणा की थी और उस दिन भी स्टॉक 1 प्रतिशत बढ़कर बंद हुआ था। मंगलवार को सुजलॉन एनर्जी में कई ब्लॉक डील हुई हैं। इन ब्लॉक सौदों में कंपनी के 21.9 लाख शेयर या 0.4 प्रतिशत इक्विटी का आदान-प्रदान हुआ है, जिसकी वैल्यू लगभग 90 करोड़ बताई जा रही है। बता दें कि यह ट्रांजैक्शन 68 प्रति शेयर की औसत कीमत पर हुई है। सुजलॉन एनर्जी ने हाल ही में 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 302 करोड़ रुपये की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की।

Applications Invited From NEET UG Female Qualifiers For Armed Forces Medical Services

Indian Army has invited applications from interested and eligible candidates for Armed Forces Medical Services (AMS). Female candidates who have qualified NEET (UG)-2024, are eligible for applying to AFMS. Candidates can register and apply at the website www.joinindianarmy.nic.in (JIA). Candidates will be shortlisted for admission at colleges of Nursing based on the final merit cum choice prepared using NEET (UG) 2024 score, Computer Based Test of General Intelligence, General English (TOGIGE), Psychological Assessment and Interview. **Eligibility-** Female candidates applying for the post should be unmarried/divorced/legally separated/ widow without encumbrances. Applicants should be born between October 1, 1999 and September 30, 2007 (both days inclusive).

Educational qualification- Candidate must have passed in first attempt, Senior Secondary Examination (10+2) or equivalent (12 years schooling), with Physics, Chemistry, Biology (Botany and Zoology) and English with not less than 50 per cent aggregate marks as a regular student from a statutory/recognised board/university/examining body.

Physical standards- Medical fitness for admission to BSc (Nursing) course will be decided by the medical board conducted as per the standards and criteria prescribed and amended from time to time. The minimum height required for entry into armed forces for female candidates is 152 cm. Candidates from Hill and North Eastern States will be accepted with a minimum height of 147cm. An allowance for growth of 2 cm will be made for candidates below 18 years at the time of examination.

Screening process- Candidates will be shortlisted for the exam based on the scores of NEET UG 2024. The shortlisted candidates will have to appear for ToGIGE, Psychological Assessment, Interview and Medical examination at Base Hospital Delhi Cantt. Test of General Intelligence and General English (ToGIGE)

Test of General Intelligence and General English (TOGIGE) is conducted in the Computer Based Test (CBT) mode consisting of 40 MCQs of two marks each for maximum marks of 80. There will be negative mark of 0.5 for every incorrect answer. These 40 questions will be required to be answered in 30 mins.

CAT 2024 Website Activated, Registrations To Begin From August 1

Indian Institutes of Management have activated the website link for the Common Admission Test (CAT) 2024. The registrations for the management entrance exam will begin from August 1 and end on September 13, 2024.

The admit cards for the exam will be out on November 5, 2024. CAT 2024 has been scheduled for November 24, 2024. IIM Calcutta is the organising institute for this exam. Interested and eligible candidates can register on the official website, iimcat.ac.in. Individuals who hold a bachelor's degree with at least 50% aggregate marks (or 45% for those in reserved categories) are eligible to apply for the exam.

The official website of the CAT 2024 reads, "The CAT 2024 advertisement has been published in several newspapers in multiple languages across the country, however the information contained in the CAT website shall be considered as final." The exam is a prerequisite for admission to various postgraduate and fellow/doctorate programmes of IIMs. The scores are also allowed to be used by listed non-IIM member institutions. CAT 2024 will be conducted on November 24 across 170 cities.

Calculation of marks

The percentage of marks a candidate has obtained will be calculated according to the method used by their respective university or institution. If grades or CGPA are awarded, the conversion to a percentage will follow the procedure specified by that university or institution. If the university or institution does not have a conversion scheme for CGPA, the equivalent percentage will be determined by dividing the candidate's CGPA by the maximum possible CGPA and multiplying the result by 100.

Education Ministry's Indian Knowledge Systems Division Releases Books, Lecture Notes

The Indian Knowledge Systems (IKS) division of the Ministry of Education released several important publications at the Akhil Bhartiya Shiksha Samagam (ABSS) 2024. Among the releases was a compilation of lecture notes from the Faculty Training Program for Master Trainers in IKS. This program, conducted in collaboration with the University Grants Commission (UGC), took place over the past year in three stages. The book includes topics such as IKS elements and principles, philosophical foundations, methods like Tantrayukti, and subject-specific content including Chemistry, Agriculture, Ayurveda, Mathematics, Nitishastra, Panchantra, and IPR in IKS, featuring contributions from 12 IKS scholars.

Another notable release is "Kautilya's Arthashastra: Timeless Strategies for Modern Governance," authored by Vinayak Rajat Bhat, Associate Professor at Chanakya University, and Tejusvi Shukla, Former Research Associate at Chanakya University. This book offers an interpretation of Kau?ilya's work on statecraft, including contemporary examples and real-world applications.

"Marma Kannadi: Decoding the Human Body the Siddha Way," authored by Gurukkal Dr. S. Mahesh, explores the teachings of sage Agasthya on marmas, the power centers in the human body. It provides insights into Siddha medicine, Kalaripayattu, and Varmakalai. Additionally, the book "Shodha Vijaya" focuses on southern dynasties with an emphasis on the Vijayanagara Karnata Kingdom. It includes research articles on topics ranging from theatre and dance to ancient scriptures.

A report on the state of the Indian Knowledge Systems and Heritage (IKS & H) Industry by professor Mohan Raghavan from IIT Hyderabad was also presented. It projects the IKS & H industry to potentially become a trillion-dollar sector within the next decade, highlighting growth potential in areas such as Culinary, Textiles, Tourism, and Ayurveda.

The ABSS 2024 highlights the significance of Indian Knowledge Systems and their contemporary relevance. The first ABSS event was held in July 2022 in Varanasi, inaugurated by Prime Minister Shri Narendra Modi. The event aims to facilitate the effective implementation of NEP 2020, strengthen links among higher educational institutions, and address challenges faced by higher education institutions.

Education Ministry announces guidelines for bagless days for Classes 6 to 8 students

The Union Ministry of Education on Monday announced the guidelines for the implementation of bagless days for classes 6 to 8 and making learning in schools more joyful, experiential and stress-free. The guidelines, developed by PSS Central Institute of Vocational Education, a unit of the National Council for Educational Research and Training (NCERT), were released on the fourth anniversary of the new National Education Policy (NEP), 2020. The NEP, 2020, had recommended that all students in classes 6-8 participate in a 10-day bagless period.

"The idea behind 10 bagless days is to make them an integral part of the teaching learning process rather than an add-on to the existing scheme of studies of education from classes 6-8. It will not only reduce the boundaries between the bookish knowledge and application of knowledge but also expose children to the skill requirements in the work areas, thus helping them to decide the future career path," the guidelines stated. "Every student will take a fun course during classes 6-8 that gives a survey and hands-on experience of a sampling of important vocational craft such as carpentry, electric work, metal work, gardening, pottery making, etc, as decided by states and local communities and as mapped by local skilling needs," they added.The ministry said all students would participate in the 10-day bagless period sometime during classes 6-8 during which they would intern with local vocational experts such as carpenters, gardeners, potters, etc. "Ten bagless days activities can be accommodated in any number of slots in an annual calendar. But it is advisable to keep two or three slots. While developing an annual work plan, all subject teachers may be involved. If necessary, indoor and outdoor activities may be clubbed in a day," the guidelines stated. Visit and survey of vegetable markets; charity visits; survey and report writing on pet care; doodling, kite making and flying; organising a book fair; sitting under a banyan tree; and visiting a biogas plant and solar energy park are among the recommended activities in the NCERT guidelines. Among other initiatives launched on the NEP anniversary were dedicated TV channels to facilitate learning of various Indian languages; a Tamil channel; primers for early graders in 25 Indian languages; career guidance guidelines; National Mission for Mentoring and National Professional Standards for Teachers in braille and audiobooks; school innovation marathon by the All India Council for Technical Education (AICTE) and a book on graduation attributes and professional competencies. Four books and lecture notes aimed at promoting Indian knowledge systems among students and teachers were also launched.

Factor in Class 9 to 11 marks for Class 12 report card: Govt proposal

A student's performance — based on both exams and continuing classwork — in Classes 9, 10, and 11 should be counted towards their final marks at the end of Class 12, according to a report recently submitted to the Education Ministry by PARAKH, a unit set up in NCERT last year to standardise assessment by school boards across the country.

In line with the National Education Policy, PARAKH's mandate included capacity development, achievement surveys, equivalence of school boards a common assessment standards.

After discussions with 32 school boards over the past year, PARAKH has submitted a report to the Education Ministry this month recommending measures to align evaluation of all school boards. One key recommendation is to include performance from Classes 9, 10, and 11 in the final Class 12 report card, with a weight of 15% for Class 9, 20% for Class 10, 25% for Class 11, and 40% for Class 12.

According to the PARAKH report, evaluation should be a combination of formative assessments (continuous classroom assessments through holistic progress cards, group discussions, projects) and summative assessments (term-end examinations).

The report suggests that in Class 9, 70% of the final score be drawn from formative assessments and 30% from summative assessments. In Class 10, the final score will be based 50% on formative assessments and 50% on summative assessments. For Class 11, it will be 40% formative and 60% summative assessments. In Class 12, the weight for formative assessments will drop to 30% with 70% of the final score based on summative assessments.

Sources said this report will be shared with all school boards for feedback. In fact, the first round of discussions was held last week with authorities of Haryana, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand, Uttar Pradesh and Bihar.

In this meeting, states are learnt to have argued for a different approach towards factoring in class-wise performance. Instead of integrating the performance of Classes 9, 10, and 11 into the final Class 12 report card, the states argued, 40% of the score from Class 9 and 60% from Class 10 should contribute to the final Class 10 score. Similarly, 40% of the score from Class 11 and 60% from Class 12 should contribute to the final Class 12 score.

PARAKH will now hold discussions with the remaining school boards in August. The holistic progress card for classes 9 to 12, which will play a role in the formative assessments, has already been designed by PARAKH and includes the student's evaluation of themselves in aspects like "time management", teacher's assessment of the student in group project work, and peer feedback.

In its recommendations, PARAKH has also suggested that the assessments be in terms of credits: a student can earn 40 credits in Classes 9 and 10 each, and 44 credits in Classes 11 and 12 each. In Classes 9 and 10, 32 credits will be subject-specific (12 credits in three languages; four credits in mathematics; four for science, four for social science etc). Recommendations include that boards should develop a system of credit transfer in line with the National Credit Framework.

A government official said that the concept of credits suggested by PARAKH is in line with the mention of the 'Academic Bank of Credits' in NEP 2020, and that this is the basis of the proposal to "credit" a student's achievements at the secondary level and amalgamate that with the board exam performance. Officials said this transition cannot be "abrupt" and hence deliberations with states are on to address any misgivings and arrive at a consensus.

पर्यावरण प्रेमी नीली चिड़िया है वर्डिटर फ्लाईकैचर

पर्यावरण प्रेमी मोरगला पतेना या वर्डिटर फ्लाईकैचर उन पंछियों में से एक हैं जो पूरे भारत-वर्ष में पाई जाती हैं। ये पंछी हर साल सर्दियों में हिमालय की गोद से निकल कर दक्षिण भारत चले जाते हैं और फिर गर्मियां आते ही लौट आते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें।

ऊंची डाली पर ही बैठती है

गहरे नीले रंग के पंखों से लदी यह चिड़िया अक्सर हवा में उड़ती हुई नीली गेंद की तरह प्रतीत होती है। आंख के पास काले भाग और स्लेटी-वेंट को छोड़कर, वयस्क नर पक्षी का शरीर गहरे नीले रंग का होता है। अक्सर यह पंछी ऊंची डाली और पेड़ की शीर्ष शाखाओं पर बैठे हुए दिख जाते हैं।

भारत में बसना है पसंद

शीत ऋतु के शुरू होते ही यह पंछी भारत के उत्तरी इलाकों से निकल कर दक्षिण की और रवाना हो जाते हैं। उत्तर में दिल्ली, पंजाब से लेकर, दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, गुजरात से बंगाल तक सब जगह इस पछी को देखा जा चुका है। इनके खूबसूरत नीले रंगों का हर एक प्रकृति प्रेमी दीवाना है। यह कप के आकार का घोंसला बनाते हैं और इनके अंडों का रंग सफेद होता है, जिनके कुंद-अंत पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं। मादा पंछी एक बार में 3 से 5 अंडे तक दे सकती है।

खुराक में खाते हैं कीड़े-मकोड़े

पक्षी की कीड़े-मकोडे इनकी खुराक का मुख्य हिस्सा होते हैं। ये पंछी अक्सर उड़ते हुए कीड़े-इत्यादि को हवा में ही पकड़ कर खाते हैं। इस प्रजाति की संख्या काफी ज्यादा हैं. जिसकी वजह से इस प्रजाति को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) लाल सूची के अनुसार खतरे से बाहर वाली श्रेणी में रखा गया है। इनकी औसत उम्र 9 साल तक हो सकती हैं।

इस आइलैंड पर आज भी इस्तेमाल होते हैं पत्थर के सिक्के

सदियों से चली आ रही है परंपरा

इंसान सदियों से करेंसी यानी मुद्रा का इस्तेमाल खरीद-फरोख्त और कारोबार के लिए करता आया है। एक दौर था जब महंगे रत्नों में कारोबार हुआ करता था। लोग मोती, कौड़ियां और दूसरे रत्न देकर चीजें खरीदा करते थे। फिर सिक्कों का चलन शुरू हुआ। सोने-चांदी, तांबे, कांसे और अल्यूमिनियम के सिक्के तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं में ढाले गए। सिक्कों के साथ ही नोटों का चलन भी शुरू हुआ। पर, क्या कभी आपने करेंसी के रूप में बड़े-बड़े पत्थरों के इस्तेमाल की बात सुनी है? नहीं न! तो, चलिए आज आप को ऐसी जगह की सैर पर ले चलते हैं, जहां की करेंसी पत्थर है और सदियों से ऐसा होता आ रहा है।

इसके लिए आप को प्रशांत महासागर के माइक्रोनेशिया इलाके में जाना पड़ेगा। यहां पर बहुत छोटे-छोटे जजीरे आबाद हैं। इन्हीं में से एक द्वीप है यप। ये छोटी सी जगह है, जहां कुल मिलाकर 11 हजार लोग रहते हैं। मगर इसकी शोहरत ऐसी है कि 11वीं सदी में मिस्र के एक राजा के हवाले से यप का जिक्र मिलता है। इसी तरह मशहूर यूरोपीय यात्री मार्को पोलो ने तेरहवीं सदी में लिखी अपनी एक किताब में इसका जिक्र किया है। इन दोनों ही मिसालों में कहीं भी यप का नाम नही लिखा है। मगर दोनों साहित्यों में एक ऐसी जगह का जिक्र है, जहां की करेंसी पत्थर हुआ करती थी।

जब आप यप पहुंचेंगे, तो आपका सामना घने जंगलों, दलदले बागों और बेहद पुराने दौर के हालात से होगा। दिन भर में सिर्फ एक फ्लाइट है, जो यप के छोटे से हवाई अड्डे पर उतरती है। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही आप को कतार से लगे छोटे-बड़े ढले हुए पत्थर दिखेंगे। इनके बीच मे छेद होता है, ताकि इन्हें कहीं लाने-ले जाने में सहूलियत हो। पूरे यप द्वीप पर ऐसे छोटे-बड़े पत्थर जहां-तहां पड़े दिख जाते हैं।

यप द्वीप की मिट्टी दलदली है। यहां चट्टानें नहीं हैं। फिर भी पत्थर की इस करेंसी का चलन यहां सदियों से है। किसी को नहीं पता कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। लेकिन, स्थानीय लोग बताते हैं कि आज से सैकड़ों साल पहले यप के बाशिंदे डोंगियों में बैठकर चार सौ किलोमीटर दूर स्थित पलाऊ द्वीप जाया करते थे। वहां से वो चट्टानें

काटकर ये पत्थर तराशा करते थे। फिर इन्हें नावों में लाद कर यहां यप लाया जाता था। इन्हें राई कहा जाता है। पिछली कई सदियों से इन पत्थरों को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। पहले यप के आदिवासी इन पत्थरों को बड़े बेढंगे तरीके से काटकर यहां लाते थे। फिर हथियारों के विकास से पत्थरों को सुघड़ तरीके से ढालकर यहां लाया जाने लगा।

उन्नीसवीं सदी में जब यप पर स्पेन का कब्जा हो गया, तब भी यहां पर पत्थरों से कारोबार थमा नहीं। जब पलाऊ जाने वाले नाविक अपने साथ ढले हुए पत्थर लाते थे, तो वो इन्हें यप के बड़े सरदारों को सौंप देते थे। फिर वो सरदार इन पत्थरों को अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम देकर लाने वाले को सौंप देते थे। पांच में से दो पत्थर ये सरदार खुद शुरुआत में पत्थरों की कीमत सीपियों की संख्या से तय होती थी क्योंकि पत्थरों से पहले सीपी को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जैसे एक पत्थर के बदले पचास सीपी दी जाती थीं। आज फुटकर करेंसी के तौर पर यप में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल होता है। लेकिन, इन पत्थरों की यप समाज में अपनी अहमियत बरकरार है। आज हर पत्थर का इतिहास है। उससे जुड़ा कोई न कोई किस्सा है। किसी भी परिवार के पास ये करेंसी होना बहुत सम्मान

की बात मानी जाती है।

आज इन पत्थरों की करेंसी का इस्तेमाल रोजाना के लेन-देन में नहीं होता। बल्कि समाज में इसे कभी माफीनामे और कभी शादी-संबंध को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। पत्थर के इन सिक्कों का आकार सात सेंटीमीटर से लेकर 3.6 मीटर तक होता है। इन सिक्कों का मोल इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस काम में इस्तेमाल होता है और किसको दिया जाता है। कबीले के सरदार, आने वाली नस्लों को पत्थर के हर सिक्के का इतिहास बताते हैं।

यहां पिछले 200 सालों से पत्थर की इन करेंसी का इतिहास आने वाली नस्लों को जबानी याद कराया जा रहा है। अब पत्थर के इन सिक्कों को एक म्यूजियम में रखा गया है। जहां टूटे-फूटे पत्थर की इन करेंसी का भी इतिहास दर्ज किया गया है। ये किस गांव के हैं, इनका किस परिवार से नाता है।

अब भी कुछ नए पत्थर के सिक्के ढाले जा रहे हैं। मगर अब इनकी तादाद बहुत कम हो गई है। दिलचस्प बात ये है कि इन बहुमूल्य सिक्कों को चुराए जाने का डर नहीं है। जैसा कि नोटों या सिक्कों के साथ हो सकता है। ये इतने बड़े हैं और सब को इनके बारे में मालूम है, तो कोई इन्हें चुराकर ले भी कहां जा सकता है। आज पत्थर की ये करेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के तौर पर नई नस्ल को सौंपी जा रही है।

दुनिया की खतरनाक मकड़ियों में शामिल है फनेल वेब स्पाइडर

हमारी पृथ्वी पर ऐसे कई जीव पाए जाते हैं, जिनमें पाए जाने वाला जहर इंसानों को पलभर में मौत की नींद सुला सकता है. इन जीवों के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में सांप या बिच्छू का ख्याल आया होगा, लेकिन आज हम आपको दुनिया की पांच बेहद ही खतरनाक मकड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं. जिनके काटे जाने के बाद मौत को टालना मुश्किल हो जाती है.

इस मकड़ी का नाम फनेल वेब स्पाइडर है। यह दुनिया की खतरनाक मकड़ियों में शामिल है। अगर ये किसी को काट ले तो उसकी 15 मिनट में मौत हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में इसके काटने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना इस मकड़ी के जहर की काट के लिए कोई असरदार दवा भी नहीं है। इस मकड़ी के काटते ही व्यक्ति का उसकी मांसपेशियों पर नियंत्रण खत्म हो जाता है और व्यक्ति की मौत पलभर में हो जाती सिडनी फनल वेब- ये दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक मकड़ी है. इसका नाम दुनिया की सबसे घातक मकड़ियों में शुमार किया जाता है. इसके शरीर का आकार एक फनल की तरह होता है, जिस कारण इसे सिडनी फनल कहा जाता है. ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाई जाने वाली यह मकड़ियां आग लग जाने की वजह से जमीन के अंदर छिप गई थीं। लेकिन तेज बारिश के बाद बाढ़ आई तो ये बाहर आ गईं। इसके बाद ये मकड़ियां आबादी वाले इलाकों में पहुंच गईं और कई शहरों में अपना ठिकाना बना लिया। अगर यह मकड़ी किसी को काट लेती है, तो उसके शरीर पर लाल रंग का निशान बन जाता है और चकत्ते पड़ जाते हैं। उसको तेज दर्द होता है और लगातार उल्टियां होने लगती हैं। इसके अलावा इसान का ब्लड प्रेशर भी काफी बढ़ जाता है। मकड़ी के काटने के बाद व्यक्ति भयानक दर्द से छटपटाने लगता है और 15 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाती है। बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सबसे ज्यादा जहरीली मकड़िया पाई जाती हैं। वैज्ञानिक इस मकड़ी के जहर को निष्प्रभावी बनाने की दवा बनाने में जुटे हैं और उनको जल्द ही इसमें कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा भी दुनिया में कई जहरीली मकड़ियां पाई जाती हैं जिनके काटने से किसी की भी मौत हो सकती है।

दुनिया के अजीबों गरीब टैक्स, मुस्कुराओ या कंफ्यूज़ हो जाओ

इस दुनिया में आए हैं, तो टैक्स तो देना पड़ेगा. चाय, बिस्कुट या हो कोई महंगी चीज़ आप हर चीज़ के लिए टैक्स देते हैं. अगर सैलरी अधिक है तो उनको तो देना ही देना है.

हम सब जानते हैं कि इनके लिए टैक्स देना पड़ता है. लेकिन कुछ-कुछ टैक्स का मतलब समझ पाना मानो असंभव सा लगता है. दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें है, जहां सरकार बेफ़िज़ूल की चीज़ों पर टैक्स लगा कर लोगों से पैसे ले रही है सरकारें. ख़ास बात ये है कि इन टैक्स के नाम पढ़कर शायद आप मुस्कुराओ या कंफ्यूज़ हो जाओ. चलिए इसी क्रम में दुनिया के कोने-कोने से अजीबों गरीब टैक्स की लिस्ट लेकर आए हैं जो अगर नहीं होते, टैक्स जैसी चीज़ मज़ेदार नहीं लगती. नज़र डालते हैं इन अजीबो गरीब टैक्स की लिस्ट पर

टैटू टैक्स

क्या आपने कभी सुना है की टैटू बनवाने के लिए भी टैक्स देना ज़रूरी होता है? लोग टैटू अपने शरीर पर कुछ यादों को छपवाने के लिए बनवाते हैं. लेकिन इसके लिए भी उन्हें एक कीमत चुकानी पड़ती है. संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित अर्कांसस 2002 से विभिन्न टैटू स्टूडियो से सेल्स टैक्स लेता है.

बैचलर टैक्स

क्या मतलब कोई अपनी मर्ज़ी से अकेले भी नहीं रह सकता है क्या? ये टैक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसौरी में लिया जाता है. यहां 21 साल से 50 साल के बैचलर पुरुषों से 1 डॉलर टैक्स लिया जाता है.

कद्दू टैक्स

कद्दू सुनते ही दिमाग में हैलोवीन का त्योहार आ जाता है. जहां लोग खूब सजते और संवरते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्यू जर्सी (संयुक्त राज्य अमेरिका) में कद्दू एक कर-मुक्त खाना है, लेकिन अगर इसे पेंट, वार्निश या काटकर और सजावट के रूप में बेचा जाता है, तो इसपर सेल्स टैक्स लगता है.

खिड़की टैक्स

इस टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स भी कहा जाता है. इस टैक्स को लगाने का एक ही उद्देश्य था. इस टैक्स में लोगों के घरों में कितनी खिड़कियां हैं, उसपर लगता था. ताकि अमीर और गरीब का पता लगाया जा सके. लेकिन बाद में इन देशों द्वारा इस तरह के करधन के ख़िलाफ़ बहुत से आंदोलन के कारण इसे ख़त्म कर दिया गया था.

टॉयलेट फ्लश टैक्स

पानी के ख़र्च पर नज़र रखने के लिए ये टैक्स मैरीलैंड में लगाया था. जहां 5 डॉलर प्रति माह का टैक्स लगता है. जो बाद में मैरीलैंड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम में जाता है.

ब्लूबेरी टैक्स

ब्लूबेरी टैक्स फलों की अधिक कटाई को रोकने के लिए लगाया जाता है. जो बदले में वनस्पति को पनपने में मदद करता है. यूनाइटेड स्टेट्स के मेन में काफ़ी ज्यादा है. इसीलिए मेन में, ब्लूबेरी के उत्पादन पर प्रति पाउंड डेढ़ पैसा टैक्स लगाया जाता है.

प्लेइंग कार्ड टैक्स

एक कारण है कि अलबामा अपने कैसीनो के लिए क्यों नहीं जाना जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण टैक्स है. अलबामा संघ का एकमात्र राज्य है जिसने राज्य के भीतर ख़रीदे गए कार्डों के डेक के लिए 10% प्लेइंग कार्ड टैक्स चार्ज करता है.

कैंडी टैक्स

कोई टॉफ़ी और कैंडी पर कैसे टैक्स लगा सकता है? लेकिन Chicago में ऐसा होता है. कैंडी अगर मैदा या आटा से बनी हो, तो उसपर साधारण टैक्स लगता है. वहीं अगर कैंडी बिना मैदा के बनती है, तो उसपर 5.25% का टैक्स लगाया जाता है.

फैट टैक्स

भारत के केरल राज्य में 14.5% का टैक्स लिया जाता है. ताकि लोग कम मात्रा में जंक खाना खाएं और अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें.

एंटरटेनमेंट टैक्स

फैट टैक्स ही नहीं, बल्कि भारत में एंटरटेनमेंट टैक्स भी लिया जाता है. हां, एक स्पेशल तरह का टैक्स है, जो स्पोर्ट्स इवेंट, मूवीज़ और थिएटर शो पर लगता है जो हर एक राज्य में अलग-अलग होता है.

संक्षिप्त समाचार

16 साल की जिया ने रचा इतिहास

नई दिल्ली, एजेंसी। जिया ने 28 से 29 जुलाई के बीच 17 घंटे और 25 मिनट के समय में इंग्लैंड के एबट्स क्लिफ से फ्रांस के प्वाइंट डे ला कोर्टे-ड्यून तक इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। उन्होंने 34 किलोमीटर की दूरी तय की।

'ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर' से पीड़ित मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 28-29 जुलाई को हासिल की। जिया ने 28 से 29 जुलाई के बीच 17 घंटे और 25 मिनट के समय में इंग्लैंड के एबट्स क्लिफ से फ्रांस के प्वाइंट डे ला कोर्टे-ड्यून तक इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। उन्होंने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। वह मुंबई में सेवारत नौसेना के मदन राय की बेटी हैं। पश्चिमी नौसेना कमान (डब्ल्यूएनसी) ने युवा पैरा तैराक को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

पश्चिमी नौसेना कमान ने 'एक्स' पर लिखा, डब्ल्यूएनसी के सभी कर्मचारी जिया राय को इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनने पर हार्दिक बधाई देते हैं।

सीन नदी को लेकर विवाद जारी, पानी की खराब गुणवत्ता के कारण लगातार दूसरे दिन तैराकी अभ्यास रद्द

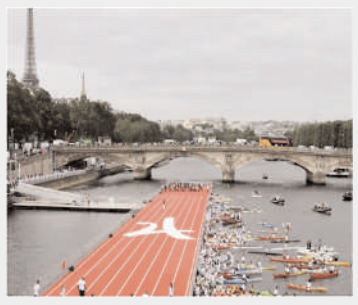

पेरिस, एजेंसी। सीन नदी में पानी की खराब गुणवत्ता के कारण अधिकारियों ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन ओलंपिक ट्रायथलॉन के तैराकी सत्र को रद्द कर दिया। पेरिस खेलों में आयोजन की देखरेख करने वालों को हालांकि उम्मीद है कि मंगलवार को प्रतियोगिता शुरू होने पर ट्रायथलीट शहर के प्रसिद्ध जलमार्ग में तैरने में सक्षम होंगे। ट्रायथलॉन में खिलाड़ियों को दौड़ने के साथ साइकिल रेस और तैराकी करनी पड़ती है।

इस खेल की वैश्विक शासी निकाय 'वर्ल्ड ट्रायथलॉन' की मेडिकल टीम और शहर के अधिकारियों को उम्मीद है कि मंगलवार को प्रतियोगिता से पहले धूप निकलने और तापमान बढ़ने के बाद नदी के पानी में ई. कोली और अन्य बैक्टीरिया का स्तर आवश्यक सीमा से नीचे चला जाएगा। वर्ल्ड ट्रायथलॉन ने सीन में पानी की गुणवत्ता पर एक बैठक के बाद सोमवार तड़के तैराकी अभ्यास को रद्द करने का निर्णय लिया। शुक्रवार को उद्घाटन समारोह में बारिश ने खलल डाला और शनिवार को भी बारिश जारी रही, जिससे कुछ टेनिस मैच और स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता स्थगित करनी पड़ी।

पेरिस ओलंपिक

अर्जुन बबूता का युग 2025 में शुरू होगा: कोच दीपाली देशपांडे

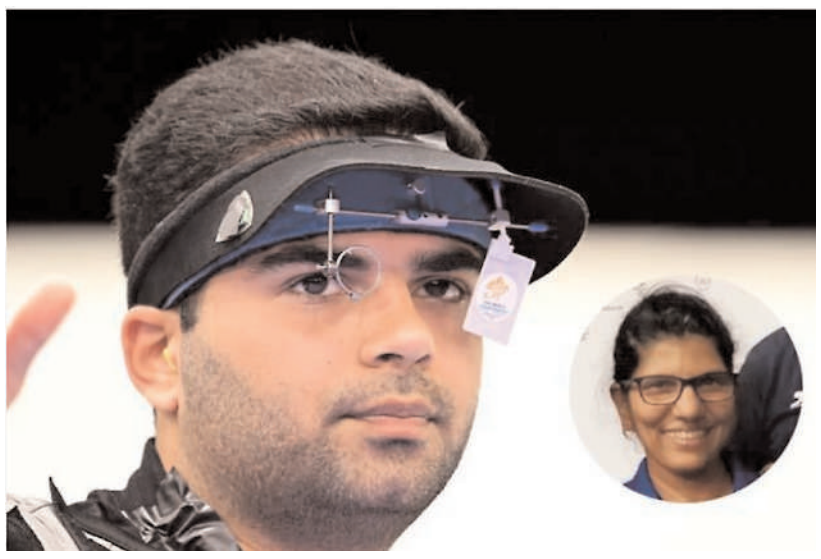

नई दिल्ली, एजेंसी। पेरिस ओलिम्पिक खेलों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अर्जुन बबूता के चौथे स्थान पर आने के सदमे से उबरने में कोच दीपाली देशपांडे को एक घंटे का समय लगा। हजारों मील दूर बैठी दीपाली अपने सबसे मेहनती शिष्यों में से एक के दर्द को महसूस कर सकती थी जब वह अपने पहले ही ओलिम्पिक में पदक जीतने के इतने करीब था लेकिन भारी दबाव के बीच चौथे स्थान पर रहा। बबूता जब 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय टीम में आया था तब से उसे कोचिंग दे रही दीपाली को एक ऐसा निशानेबाज मिला जिसकी मुद्रा (पॉस्चर) 'बहुत खराब थी लेकिन उसकी नजर सटीकता और परफेक्ट होने पर थी।

वर्ष 2015 में जसपाल राणा के साथ जूनियर कोचिंग टीम का हिस्सा रही दीपाली को भरोसा है कि बबूता जल्द ही इस झटके से उबर जाएगा और 2028 लॉस एंजिल्स ओलिम्पिक की ओर उनका सफर पेरिस के पास शेटराउ निशानेबाजी रेंज में होने वाले घटनाक्रमों से प्रेरित होगा। बबूता एक समय रजत पदक जीतने की स्थिति में दिख रहे थे लेकिन घबराहट में खराब निशाना लगा बैठे। बुसान 2002 एशियाई खेलों की निशानेबाजी टीम स्पर्धा की रजत पदक विजेता दीपाली ने पिछले नौ साल में बबूता को परिपक्व होते हुए देखा है।

दीपाली ने कहा कि वह बहुत बुरे दौर से गुजरा था जब उसे पीठ में चोट लगी थी जिससे 3 साल पहले टोक्यो ओलिम्पिक में जगह बनाने की उसकी उम्मीदें खत्म हो गई थीं। निशानेबाजी के दौरान वह 2 बार रेंज में गिर गया था क्योंकि उसके पैर सुन्न हो जाते थे। जब बबूता को पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी गई थी तब भी दीपाली को उनकी क्षमताओं पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने उसे आराम करने और ठीक होने का समय दिया लेकिन हर बार वह फोन करके पूछता था कि क्या मैं (बबूता) ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूं और हर बार मुझे उसे बताना पड़ता था कि उसे पहले फिट होने की जरूरत है। दीपाली ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए भी मुश्किल था और मैंने उसे फाइनल में दूसरे से चौथे स्थान पर आते देख अपना फोन फेंक दिया। मुझे पता है कि मैंने उसके जूनियर दिनों के दौरान उसके साथ कितनी मेहनत की है और चोट के दौर से गुजरने में उसकी कितनी मदद की है। उन्होंने कहा कि वह उन लोगों में से एक है जो फाइनल में लगातार 10.8 अंक बना सकता है और मुझे यकीन है कि उसका युग 2025 में शुरू होगा। निशानेबाजी के खेल के प्रति बबूता के प्यार ने उनके पिता को ओलिम्पिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा से मिलने का समय लेने के लिए प्रेरित किया।

उस मुलाकात ने किसी दिन इस चैंपियन की तरह बनने की इच्छा को जन्म दिया और यही बबूता के लिए इन सभी वर्षों में प्रेरणा शक्ति रही। बबूता ने सोमवार को स्वीकार किया कि बिंद्रा ने उन पर कितना गहरा प्रभाव डाला है। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कल और आज भी बात की। वह खेल गांव में आए थे और अपने विचार साझा किए। उन्होंने मुझे वर्तमान में रहने के लिए कहा। हम हमेशा वर्तमान में रहने की कोशिश करते हैं लेकिन जब बिंद्रा जैसे सीनियर खिलाड़ी ऐसा कहते हैं तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। बाबूता ने सोमवार को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित वर्चुअल बातचीत में कहा कि उन्होंने मुझसे कहा 'मैं भी चौथे स्थान पर था (2016 रियो में) और मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। उन्होंने कहा- उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आज निश्चित रूप से रो सकता हूं लेकिन मुझे आगे बढ़ना होगा।

भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बिंद्रा के साथ अपनी बातचीत के बारे में बबूता ने कहा कि उन्हें मेरे से बहुत उम्मीदें हैं। पिछले दो दिनों में अपनी प्रतिस्पर्धा के बारे में उन्होंने कहा कि यह उतार-चढ़ाव भरा रहा। यहां निशानेबाजों का स्तर अच्छा है। लेकिन भारतीय अब ऐसी स्थिति में हैं जहां हम सिर्फ ओलिम्पिक के लिए क्वालीफाई करने के बारे में नहीं सोचते बल्कि पदक जीतने का लक्ष्य रखते हैं। हर कोई सक्षम है और हर कोई (निशानेबाजी टीम में शामिल) पदक जीत सकता है।

भारतीय स्टार मनिका ने फ्रांस की प्रीथिका को 4-0 से हराया, राउंड 16 में पहुंची

पेरिस, एजेंसी। मनिका बत्रा का पेरिस ओलंपिक में दमदार प्रदर्शन जारी है। सोमवार को भारतीय खिलाड़ी ने फ्रांस की प्रीथिका पावड़े को लगातार चार गेमों में हराकर महिला एकल के राउंड 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। बत्रा ने 11-9, 11-6, 11-9, 11-7 से राउंड 32 में पावड़े को हराया। अपनी इस जीत के साथ मनिका ओलंपिक में राउंड 16 के दौर में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। टूर्नामेंट में 18वीं वरीयता प्राप्त और विश्व में 28वें स्थान पर काबिज 2018 राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन मनिका ने इससे पहले पेरिस ओलंपिक में विश्व की 103वें नंबर की खिलाड़ी ग्रेट ब्रिटेन की अन्ना हर्सी पर 11-8, 12-10, 11-9, 9-11, 11-5 अपनी पहली जीत हासिल की थी। मनिका को पहले गेम में बायें हाथ की खिलाड़ी के खिलाफ सामंजस्य बिठाने में परेशानी हुई और यह काफी करीबी मुकाबला रहा। मनिका ने अखिरी तीन अंक अपने नाम कर इसे 11-9 से जीता।

दूसरे गेम की शुरुआत में भी मुकाबला काफी करीबी था, लेकिन 6-6 की बराबरी के बाद मनिका ने प्रीथिका को कोई मौका नहीं दिया और 11-6 से वह जीत गई। भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे गेम की लय तीसरे गेम में जारी रखते हुए पांच अंक की बढ़त बनाई, लेकिन प्रीथिका ने लगातार चार अंक हासिल कर स्कोर को 9-10 कर दिया। प्रीथिका दबाव में गेंद को नेट पर खेल गई और मनिका ने 11-9 से इस गेम को जीत लिया। मनिका ने चौके गेम में 6-2 की बढ़त के साथ अच्छी शुरुआत को 10-4 में बदल कर छह मैच प्वाइंट हासिल किए। प्रीथिका तीन मैच प्वाइंट बचाने में सफल रही, लेकिन मनिका ने चौथे अंक को भुनाकर मैच अपने नाम किया। प्री क्वार्टर फाइनल में मनिका की भिड़ंत जापान की आठवीं वरीय हिरोनो मियू और हांगकांग की झू चेंगझू के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगी।

भारत 2025 पुरुष टी20 एशिया कप की मेजबानी करेगा, बांग्लादेश होगा वनडे प्रारूप में 2027 संस्करण का मेजबान

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत 2025 में टी20 फॉर्मेट में पुरुष एशिया कप की मेजबानी करेगा, जबकि बांग्लादेश 2027 में इस टूर्नामेंट के 50 ओवर के संस्करण की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से 50 ओवर प्रारूप में 2023 का पुरुष एशिया कप आयोजित किया था, जिसमें भारत विजेता रहा था।

भारत ने इससे पहले केवल एक बार 1990/91 में पुरुष एशिया कप की मेजबानी की थी, जिसमें वह कोलकाता के ईडन गार्डन में चैंपियन बना था। टेंडर डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया है कि पुरुष एशिया कप के दोनों भविष्य के संस्करणों में प्रति संस्करण 13 मैच होंगे। महिला टी20 एशिया कप 2026 में खेला जाएगा, हालांकि स्थान का नाम नहीं बताया गया है, इसमें कुल 15 मैच होंगे। टेंडर डॉक्यूमेंट में पुरुष अंडर-19 एशिया कप भी शामिल है, जो क्रमशः 2024, 2025, 2026 और 2027 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक संस्करण में 15 मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप, 2024 और 2026 (टी20), 2025 और 2027 (50 ओवर) , में भी 50 ओवर और टी20 के 30 मैच शामिल हैं। टेंडर राइट साइकिल में महिला इमर्जिंग टीम एशिया कप के दो संस्करण भी हैं - जिसमें 2025 और 2027 में क्रमशः प्रत्येक संस्करण में 15 मैच खेले जाएंगे।

शर्त पर आईपीएल-2025 में खेलेंगे धोनी

बीसीसीआई पर टिका फैसला

नईदिल्ली, एजेंसी। एमएस धोनी आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बतौर कप्तान नहीं बल्कि एक खिलाड़ी के रूप में खेलते हुए दिखाई दिए थे. 2024 के आईपीएल से पहले धोनी ने कप्तानी का पद छोड़ दिया था और युवा रुतुराज गायकवाड़ को चेन्नई की कमान सौंपी गई थी. आईपीएल 2024 को काफी वक़्त गुज़र चुका है, लेकिन इस बात को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पाया है कि माही अगले सीज़न में खेलेंगे या नहीं. अब सामने आई रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे धोनी का अगला आईपीएल खेलने का फैसला एक शर्त पर टिक गया है.

माही के अगले सीज़न खेलने का फैसला बीसीसीआई पर टिकता हुआ दिख रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर बीसीसीआई आईपीएल में टीमों को 5-6 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत देती है, तभी धोनी का एक खिलाड़ी के रूप में खेलते रहना जारी रह सकता है. बता दें कि 2025 से पहले आईपीएल का मेगा ऑक्शन होना है. मेगा ऑक्शन से पहले इस बात की चर्चा ज़ोरों पर कि आईपीएल टीमें बीसीसीआई से 4 से ज़्यादा खिलाड़ी रिटेन करने की मांग कर रही हैं. मौजूदा वक़्त में टीमें मेगा ऑक्शन से पहले सिर्फ 4 खिलाड़ियों को ही रिटेन कर सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई मेगा ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों की रिटेन पॉलिसी में बदलाव करती है या नहीं.

गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई का कैसा रहा प्रदर्शन

गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में कदम नहीं रख पाई थी. टीम प्वाइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर रही थी. चेन्नई ने 14 में से 7 मैच जीते और 7 गंवाए थे.

भले ही चेन्नई ने प्लेऑफ में जगह न बनाई हो, लेकिन कप्तान रुतुराज गायकवाड़ की तरफ से बैटिंग और कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था. अब अगले सीज़न में फिर गायकवाड़ पर सभी की नज़रें होंगी. फैंस देखना चाहेंगे कि क्या गायकवाड़ धोनी और चेन्नई की लिगेसी बरकरार रख पाएंगे या नहीं.

चीन ने गोताखोरी में 49वें स्वर्ण के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ा, ओलंपिक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया

पेरिस ओलंपिक

पेरिस, एजेंसी। इस मामले में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) को स्पष्टीकरण देना पड़ा। कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक अमेरिका के नाम भी गोताखोरी में 49 स्वर्ण है लेकिन आईओसी ने अमेरिका द्वारा 1904 ओलंपिक में 'प्लंजिंग फॉर डिस्टेंस' में जीते स्वर्ण को गोताखोरी की जगह तैराकी स्पर्धा का हिस्सा करार दिया। चीन ने लियान जुन्जी और यांग हाओ की जोड़ी की सिंक्रोनाइज्ड 10-मीटर प्लेटफार्म में सोमवार को यहां जीत के साथ ही ओलंपिक गोताखोरी में किसी देश द्वारा सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का इतिहास रच दिया।

ओलंपिक गोताखोरी में चीन का यह 49वां स्वर्ण पदक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड लंबे समय तक अमेरिका के नाम था। हालांकि, इस मामले में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) को स्पष्टीकरण देना पड़ा। कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक अमेरिका के नाम भी गोताखोरी में 49 स्वर्ण है लेकिन आईओसी ने अमेरिका द्वारा 1904 ओलंपिक में 'प्लंजिंग फॉर डिस्टेंस' में जीते स्वर्ण को गोताखोरी की जगह तैराकी स्पर्धा का हिस्सा करार दिया। चीन ने पिछले दोनों ओलंपिक में इस खेल के आठ में सात स्वर्ण पदक जीते है।

तीन दिन खत्म होने के बाद पदक तालिका की बात करें तो जापान छह स्वर्ण समेत 12 पदक के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद पांच स्वर्ण समेत 16 पदक जीत चुका मेजबान फ्रांस दूसरे, पांच स्वर्ण समेत 12 पदक जीत चुका चीन तीसरे, पांच स्वर्ण समेत नौ पदक जीत चुका ऑस्ट्रेलिया चौथे और पांच स्वर्ण समेत नौ पदक जीत चुका दक्षिण कोरिया पांचवें स्थान पर है। भारत एक कांस्य के साथ 26वें स्थान पर है। भारत के पदक का खाता निशानेबाज मनु भाकर ने खोला। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य अपने नाम किया।

मंजरी का लेडी चुलबुल पांडे अंदाज

मंजरी फडनिस को सिनेमा की बिंदास बाला के साथ साथ ओटीटी की चपल चंचला का भी खिताब मिल चुका है। हालिया रिलीज सीरीज 'फ्रीलांसर' में लोगों को उनका काम बेहद पसंद आया। उससे पहले 'मासूम' और 'मियां बीवी और मर्डर' में भी अपनी कातिलाना अदाओं से वह अपने प्रशंसकों की खूब तालियां बटोर चुकी हैं। सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई लवली वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की फिल्म 'चलती रहे जिंदगी' को अपनी अलग अलग कहानियों के लिए खूब तारीफ मिल रही है और सबसे ज्यादा तारीफ उस कहानी की हो रही है जिसमें मंजरी ने कथक डांस टीचर की भूमिका निभाई है।

इस बारे में एक बातचीत में मंजरी कहती हैं, एक ही दिन में दो फिल्में एक साथ रिलीज होना किसी भी कलाकार के लिए एक अलग ही पूर्णता का एहसास देता है। दोनों फिल्में बिल्कुल अलग अलग श्रेणियों की है और दोनों में मैंने बिल्कुल भिन्न किरदार किए हैं। एक में मैं अपने परिवार का खूब ख्याल रखने वाली नरमदिल, सहज और सरल कथक डांस टीचर बनी हूं। 'चलती रहे जिंदगी' नामक ये फिल्म कोरोना के संकट काल की कहानियां कहती है। दूसरी फिल्म 'यूपी फाइल्स' में मैं एक दबंग पुलिस अधिकारी के रोल में हूं जो वहां के मुख्यमंत्री की कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने में मदद करती है। मैं इन दोनों फिल्मों की सफलता की कामना करती हूं और दोनों फिल्मों से जुड़े सभी लोगों के लिए लाभदायक रहें।

मंजरी फडनिस की बीते शुक्रवार रिलीज फिल्म 'यूपी फाइल्स' कथित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित बताई जाती है। फिल्म में उनके जैसे ही पहनावे वाले में अभिनेता मनोज जोशी ने अभय सिंह का किरदार निभाया है जो राज्य में कानून और व्यवस्था कायम करने की मुहिम छेड़ता है।

फिटनेस गर्ल हैं शरवरी अल्फा के शूट से पहले बीच पर दौड़कर की ट्रेनिंग !

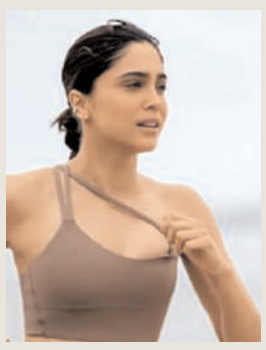

बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी ने अपने नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। कल से बहुप्रतीक्षित वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स एक्शन एंटरटेनर अल्फा की शूटिंग शुरू कर रही हैं! सुपरस्टार आलिया भट्ट के साथ अपने एड्रेनालिन पंपिंग शूटिंग शेड्यूल से एक दिन पहले, शरवरी ने मुंबई के बीच पर दौड़ते हुए अपनी सुपर-फिट बॉडी दिखाते हुए तस्वीरें पोस्ट कीं। और फिर से बड़े फिटनेस गोल्स सेट कर दिए! बॉलीवुड की उभरती स्टार ने कुछ हफ्ते पहले फिल्म के लिए ट्रेनिंग करते हुए कुछ हॉट तस्वीरें साझा कर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। लोगों ने अल्फा के लिए ट्रेनिंग के दौरान शरवरी की फिट और फैब लुक की प्रशंसा की! इस बार, शरवरी ने अपने प्रशंसकों और इंटरनेट पर लोगों से कुछ अधिक मेहनत करने और ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया है, बीच पर दौड़ते हुए उनकी तस्वीरों की एक श्रृंखला के माध्यम से। शरवरी अगली बार बहुप्रतीक्षित निखिल आडवाणी की फिल्म वेदा में नजर आएंगी, जो 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है, और फिर आदित्य चोपड़ा की अल्फा में, जिसका निर्देशन वाईआरएफ के युवा और प्रसिद्ध निर्देशक शिव रवैल कर रहे है, जिन्हें द रेलवे मेन के लिए जाना जाता है!

मसाबा मसाबा के 2 साल कंप्लीट, बरखा सिंह ने आयशा के रूप में सीरीज का हिस्सा बनने की बताई वजह

बरखा सिंह, जो एक जानी मानी बॉर्न ऑन वेब स्टार हैं, उन्हें उनकी वर्सेटिलिटी के लिए जाना जाता है। उनके द्वारा दी गई कई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के साथ, उन्होंने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों का दिल जीता है। बरखा हमेशा स्टीरियोटाइप्स को तोड़ती हैं और अपनी वर्सेटिलिटी को हर प्रोजेक्ट में पहले से ज्यादा दिखाने के लिए तैयारी करती हैं। बरखा मसाबा मसाबा में अपने आयशा के किरदार ने आउटस्टैंडिंग रोल के लिए जानी जाती हैं। बरखा सिंह ने आयशा के इस प्यारे किरदार की यादों के बारे में बात करते हुए कहा है, मसाबा मसाबा का हिस्सा बनना मेरे लिए कई वजहों से हमेशा खास रहेगा - सोनम नायर के साथ काम करना, जिनका काम मुझे ऑडिशन देने से पहले ही पसंद आ गया था, बेहतरीन कास्ट के साथ स्क्रीन शेयर करना और सच में नेटफ्लिक्स और यहां तक कि पंचमी के साथ फिर से काम करना!

संक्षिप्त समाचार

हुक्का साझा करने से इनकार करने पर भड़का शख्स, साथियों के साथ जानलेवा हमला

नईदिल्ली, एजेंसी। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में पिछले शुक्रवार को एक क्लब के बाहर एक शख्स पर कथित रूप से बेरहमी से हमला करने के आरोप में कम से कम तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि एक शख्स ने उनमें से एक के साथ हुक्का साझा करने से इनकार कर दिया था। इस पर आरोपियों ने 29 वर्षीय शख्स पर बेरहमी से हमला कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान मुख्य संदिग्ध सोनू सैनी, सूरत नगर फेज-2, सेक्टर-104 के हरेंद्र कुमार और यूपी एटा के सेक्टर 6 निवासी अमन वर्मा के रूप में की है। आरोपियों को रविवार को बजघेरा इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, घटना उस समय हुई जब न्यू पालम विहार फेज-1 निवासी पंकज शर्मा शुक्रवार सुबह करीब 5.15 बजे कॉन्सिएंट मॉल में एक क्लब से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही वह अपने स्कूटर के पास पहुंचे, छह से सात संदिग्धों ने कथित तौर पर लकड़ी के बल्लों और रॉड से उन पर हमला किया और भाग गए। क्लब के अधिकारियों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पीड़ित पंकज शर्मा को पालम विहार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जाता है कि पंकज शर्मा शुक्रवार रात करीब 1 बजे क्लब पहुंचे थे। वह हुक्का पी रहे थे, तभी सोनू सैनी उनके पास आया और उसने हुक्का पीने की इच्छा जताई। इस पर शर्मा ने उसके साथ हुक्का शेयर करने से मना कर दिया। हालांकि सैनी लगातार इसके लिए अड़ा रहा। यही नहीं उसकी शर्मा से बहस हो गई। जब शर्मा क्लब से निकल रहा था, तो संदिग्ध ने उसका पीछा किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही पीड़ित शर्मा अपने स्कूटर के पास पहुंचा, सैनी के इशारे पर संदिग्धों ने उस पर हमला कर दिया। शर्मा पालम विहार के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। अन्य संदिग्धों की पहचान कर ली गई है। पीड़ित शर्मा को कई फ्रैक्चर और चोटें आई हैं। उनके सिर पर 16 टांके लगे हैं। शर्मा की शिकायत पर बजघेरा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में संदिग्धों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

नीट-यूजी के लिए काउंसलिंग 14 अगस्त से होगी शुरू

नईदिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा- स्नातक (नीट-यूजी) 2024 के लिए काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा सोमवार को जारी नोटिस के अनुसार काउंसलिंग के लिए पंजीकरण अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। एनएमसी के सचिव डॉ. बी. श्रीनिवास ने कहा, देशभर के लगभग 710 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1.10 लाख एमबीबीएस सीटों के आवंटन के लिए काउंसलिंग होगी। साथ ही, आयुष और नर्सिंग सीटों के साथ ही 21,000 बीडीएस सीटों के लिए भी काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। एमसीसी अखिल भारतीय कोटा की 15 प्रतिशत सीटों, सभी एम्स, जेआइपीएमईआर पांडिचेरी, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय की सीटों और शत प्रतिशत डीम्ड विश्वविद्यालय सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करेगी। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से संबंधित समाचार और नोटिस के लिए एमसीसी की वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी गई है। मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट-यूजी के परिणामों की घोषणा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने शुक्रवार को की थी। परीक्षा को लेकर सामने आई थी गड़बड़ी गौरतलब है कि पांच मई को आयोजित नीट-यूजी का रिजल्ट वैसे तो चार जून को लोकसभा चुनाव परिणामों के बीच ही जारी हो गया था। लेकिन बाद में इस परीक्षा को लेकर कई गड़बड़ियां सामने आईं। इनमें छात्रों को ग्रेस मा?र्क्स देने और परीक्षा में जुड़ी अन्य गड़बड़ियों का भी मामला था। विवाद बढ़ने पर एनटीए ने 1,563 छात्रों के ग्रेस मा?र्क्स रद्द कर दिए थे। साथ ही उन्हें बाद में फिर परीक्षा का मौका दिया गया था। इन छात्रों की परीक्षा 23 जून को आयोजित की गई थी और उनके नए सिरे रिजल्ट भी घोषित किए गए थे। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं सहित कई याचिकाओं का निपटारा कर दिया।

कार्रवाई दिखावा, हमें फिर उसी हाल में रहना होगा; प्रदर्शन कर रहे छात्रों का छलका दर्द

नईदिल्ली, एजेंसी। कोचिंग संस्थान की लापरवाही के बाद राजधानी के ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहा छात्रों का आंदोलन जारी रहा। यहां के सभी कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी बंद रही। छात्रों का कहना है कि यह सब बस कुछ दिनों का दिखावा है। दो दिन बाद हमें उसी हाल में रहना होगा। जो आज किया जा रहा है वह पहले भी तो हो सकता था। सोमवार को कोचिंग और लाइब्रेरी बंद होने से छात्रों के समक्ष पढ़ाई की भी चिंता है। छात्रों का कहना है कि जो समस्या है, उसका समाधान सुनिश्चित कर प्रशासन छात्रों को यह आश्वासन दे कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी।

कुछ कोचिंग संस्थान अपना सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए दो दिन कोचिंग को बंद किए हैं। प्रदर्शनकारी छात्र संकल्प ने बताया कि वह एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में पढ़ता है। सुरक्षा ऑडिट के लिए कोचिंग बंद की गई है। कुछ छात्रों का कहना है कि अधिकांश कोचिंग इसलिए भी बंद

की गई है कि कहीं छात्र उग्र न हो जाएं। छात्रों का उद्देश्य एक सुरक्षित वातावरण देने के प्रति कोचिंग संस्थानों की प्रतिबद्धता और छात्रों की सुरक्षा को लेकर है। प्रदर्शनकारी छात्र ब्रजेंद्र यादव का कहना है कि कोचिंग बंद होने के कारण हमारी दिक्कतें बढ़ गई है। मोटी फीस, कमरे का किराया, लाइब्रेरी का किराया देने के बाद भी यदि हम यहां पढ़ाई नहीं करेंगे तो यहां हमारा ही नुकसान होगा। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका समाधान निकाला जाए। गुस्सा और क्षोभ से भरे छात्र सोमवार सुबह से ही विरोध प्रदर्शन में बैठ गए। छात्रों ने हाथों में बैनर, मृतकों के चित्र और ग्रेफिटी बनाकर अपना विरोध जताया। छात्रों ने कहा कि उनको प्रशासन और एमसीडी के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। साथ ही मुखर्जी नगर में भी इस घटना को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्रों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शन के बीच इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों को एक तरफ से प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके इनको घेर दिया गया है और एक तरफ रास्ता बनाकर दिया गया है। छात्र कोचिंग संस्थान के समीप सड़क पर बैठकर मृतकों के परिवारों के लिए न्याय तथा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग एकेडमी में तीन छात्रों की मौत के मामले में एसयूवी ड्राइवर मनोज कथूरिया को भी गिरफ्तार किया गया है। उसने सोमवार को दिल्ली कोर्ट में कहा कि उसे छात्रों की मौजूदगी की कोई जानकारी नहीं था और उसका इरादा किसी की मौत का कारण बनने का नहीं था। माना जाता है कि कथूरिया ने शनिवार को ओल्ड राजेंद्र नगर की सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई, जिससे सड़क पर जमा हुए बारिश के पानी ने तीन मंजिला इमारत के गेट को नीचे धकेल दिया।

फिर अटकी सांसें, आधे घंटे तक स्टूडेंट्स सहित 10 लोग फंसे रहे

गौर सिटी में दो फ्लोर पर अटकी लिफ्ट

नईदिल्ली, एजेंसी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी 2 के 14 एवेन्यू में चार स्कूली बच्चों और एक महिला समेत 10 लोग लिफ्ट में फंस गए। तीसरी और चौथी मंजिल के बीच में 30 मिनट तक लिफ्ट अटकी रही। लिफ्ट के अंदर से तीसरी मंजिल पर मौजूद लोगों के चिल्लाने की आवाज सुन मेंटेनेंस टीम को सूचित किया गया। इसके बाद लोगों और मेंटेनेंस कर्मचारियों ने मिलकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। लोगों का आरोप है कि प्रबंधन द्वारा रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है। लिफ्ट के अंदर लगे सिक्योरिटी अलार्म को काफी देर तक बजाया गया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। सोसाइटी के निवासी दीपक चौहान ने बताया कि टावर एम में सोमवार सुबह करीब 730 बजे ऊपर से नीचे जाने के लिए लिफ्ट में चार स्कूली बच्चे, एक घरेलू सहायिका सहित 10 लोग लिफ्ट में सवार हुए, तभी अचानक लिफ्ट फ्री फॉल हो गई और सीधे तीसरे और चौथा फ्लोर के बीच में आकर अटक गई। काफी देर तक निवासी लिफ्ट का सिक्योरिटी अलार्म बजाते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। वहीं, तीसरे मंजिल पर मौजूद निवासियों ने लिफ्ट के अंदर से लोगों के चिल्लाने की सुनी मेंटेनेंस टीम को सूचित किया गया। तभी मेंटेनेंस टीम और निवासियों ने मिलकर लिफ्ट का गेट खोल सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

जल्द शुरू होगा दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल-1? सामने आया बड़ा अपडेट; 28 जून से है बंद

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। एक माह से बंद एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 को अगस्त के पहले सप्ताह में खोला जा सकता है। यहां से मलबा लगभग हटा लिया गया है। जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू होगा। जानकारी के अनुसार, बीते 28 जून को एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर छत (कैनोपी) का बड़ा हिस्सा गिर गया था। इसकी चपेट में आने से एक कैब चालक की मौत हो गई थी, जबकि छह लोग घायल हो गए थे। हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था। मंत्रालय की ओर से बनाई गई कमेटी भी इसकी जांच कर रही है। हादसे के तुरंत बाद से टर्मिनल-1 से विमानों का परिचालन बंद कर दिया गया था। यहां से उड़ान भरने वाले अधिकांश विमानों को टर्मिनल दो या तीन पर शिफ्ट कर दिया गया। इस हादसे के चलते बीते एक माह से दोनों टर्मिनल पर यात्रियों का दबाव काफी बढ़ गया है। यात्रियों की संख्या अधिक होने के चलते सुरक्षा जांच के लिए लंबी कतारें लग रहीं हैं। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि बीते सप्ताह घटनास्थल से मलबा हटाने की अनुमति मिल चुकी है। अधिकांश मलबा हटा लिया गया है। सफाई होने के बाद इसी सप्ताह मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा। अगस्त की शुरुआत में काम पूरा होने की उम्मीद है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से देशभर के एयरपोर्ट की मजबूती जांचने के निर्देश दिए गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के टीर्मिनल-1 की जांच दिल्ली आईआईटी की ओर से की गई है। सूत्रों ने बताया कि आईआईटी की तरफ से इसे लेकर सकारात्मक रिपोर्ट दी गई है, जिसकी वजह से टर्मिनल-1 को जल्दी खोलने का निर्णय लिया गया है। पालम एयरपोर्ट थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हादसे को लेकर पुलिस ने निर्माण कार्य से जुड़े कई अधिकारियों से पूछताछ की है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

48 साल पुरानी व्यवस्था, 13 साल से कागजों में घूम रहा ड्रेनेज मास्टर प्लान; 'सीवर टाइम बम' पर बैठी है दिल्ली

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में मानसून की दस्तक से पहले मेयर ने दावा किया था कि इस बार दिल्लीवाले बारिश का आनंद उठाएंगे। उनके इस दावे की पहली पोल गत 29 जून को खुली जब रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और जगह-जगह भीषण जलभराव हुआ। अब राजेंद्र नगर में हुई घटना ने शहर में बारिश के पानी की निकासी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यह जानकर हैरानी होगी कि राजधानी अब भी 1976 में बने ड्रेनेज सिस्टम पर आश्रित है। जिस समय ये नाले बनाए गए थे, उस दौरान दिल्ली की आबादी महज 60 लाख थी, जो अब ढाई करोड़ से ज्यादा हो गई है। इसको लेकर 13 वर्ष पहले पहल की गई, लेकिन अभी तक ड्रेनेज मास्टर प्लान योजना कागजों में घूम रही है।

राजधानी में बढ़ती आबादी को लेकर ड्रेनेज मास्टर प्लान पर 2011 में काम शुरू हुआ था। इसके लिए आईआईटी से रिपोर्ट तैयार कराई गई। जुलाई 2018 में आईआईटी ने सरकार को मास्टर प्लान की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। अगस्त 2018 में सरकार ने इसे लागू करने की बात कही, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया। गत 29 जून को सरकार ने सलाहकार नियुक्त करने के लिए निविदा जारी की है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वर्ष तक इस पर काम शुरू हो पाएगा।

वर्तमान में नाले की क्षमता से पांच गुना ज्यादा आबादी दिल्ली में है। इस कारण जलनिकासी की व्यवस्था ठप्प हो जाती है। बीते वर्ष राजधानी में बाढ़ का बड़ा कारण भी नाले की लचर व्यवस्था थी। इस बार 28 जून की पहली बारिश में ही दिल्ली में जगह-जगह पानी भर गया। राजधानी में नाला तीन हिस्सों में बांटा गया है। इनमें 200 से अधिक नाले हैं। सबसे अधिक 123 नाले नजफगढ़ ड्रेन, 44 से अधिक बारापुला और ट्रांस यमुना बेसिन में 34 से अधिक हैं। इसके जरिए ही बारिश का पानी निकलता है।

सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा: चीन का भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन कंप्लीट, पांगोंग झील के पुल पर चलने लगीं गाड़ियां

वाशिंगटन , एजेंसी। चीन ने पांगोंग झील पर 400 मीटर लंबे पुल का निर्माण पूरा कर लिया है, जिसकी उच्च-रिज़ॉल्यूशन तस्वीरें पहली बार जनवरी 2022 में प्रकाशित हुई थीं। नई सैटेलाइट तस्वीरें, जो 22 जुलाई को आई, दिखाती हैं कि पुल पर अब काली परत चढ़ा दी गई है और हल्के मोटर वाहन उस पर चल रहे हैं।यह पुल, जो 1958 से चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थित है, भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है। यह पुल चीनी बलों को पांगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट के बीच तेजी से सैनिकों को स्थानांतरित करने की सुविधा देता है।

सैटेलाइट इमेजरी विशेषज्ञ और द इंटेल लैब के शोधकर्ता डेमियन सायमन ने कहा, ÷पांगोंग झील पर नया पुल चीनी बलों को तेज़ी से सैनिकों को तैनात करने के लिए एक सीधा, छोटा मार्ग प्रदान करता है। पहले, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को संघर्ष क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए झील के पूरे पूर्वी हिस्से को पार करना पड़ता था, जो एक लंबा रास्ता था और सक्रिय संघर्ष क्षेत्र में उनकी प्रतिक्रिया समय को बाधित करता था।÷ माना जा रहा है कि नए पुल

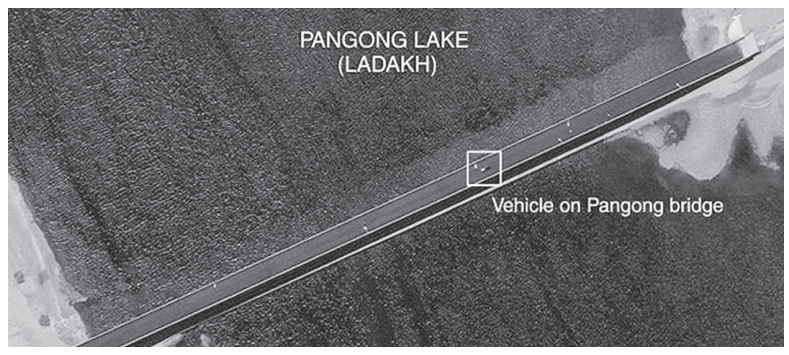

के निर्माण से झील के दोनों तटों के बीच की यात्रा दूरी लगभग 50-100 किलोमीटर या कई घंटे की यात्रा समय कम हो सकती है।

पुल के निर्माण पर प्रतिक्रिया देने के लिए पूछे जाने पर, विदेश मंत्रालय ने कहा कि ÷यह पुल उन क्षेत्रों में बनाया जा रहा है, जो लगभग 60 साल से चीन के अवैध कब्जे में हैं। लेकि भारत ने कभी भी इस तरह के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है।÷ नई सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया गया है कि पुल से जुड़ी सड़कें पहले से मौजूद सड़क नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जो पांगोंग झील के उत्तर तट पर स्थित है और खुरनाक किले तक जाती है, जो एक प्राचीन तिब्बती संरचना है। चीन ने जुलाई 1958 में खुरनाक किले पर कब्जा कर लिया था, हालांकि पहले भारतीय सेना वहां गश्त करती थी। झील के दक्षिणी तट पर एक नई सड़क का निर्माण किया गया है, जो पुल को रुतोग से जोड़ती है, जो एक चीनी गैरीसन टाउन और प्रसिद्ध हथियार भंडार है। ÷यह पुल चीन की अग्रिम और गहराई वाली सेना के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे चीन के भारत के खिलाफ अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।÷

ज्यादा खाना खिलाने से गई कुत्ते की जान, कोर्ट ने मालकिन को सुना दी सजा

बेलिंगटन , एजेंसी। न्यूजीलैंड की एक महिला को कुत्ते की मौत के बाद दो महीने की सजा सुनाई गई। दरअसल, इस महिला पर आरोप है कि उसने अपने पालतू कुत्ते को हद से ज्यादा खाना खिलाया, जिसकी वजह से उसका मोटापा बढ़ा और उसकी मौत हो गई।

रॉयल न्यूजीलैंड सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स के मुताबिक, पशु नियंत्रण अधिकारियों ने अक्टूबर 2021 में जब इस महिला के आवास पर तलाशी ली थी तो उस वक्त नुग्गी नाम के इस कुत्ते को उन्होंने वहां देखा था। इसका वजन लगभग 54 किलोग्राम (120 पाउंड था। इस वजह से कुत्ते के लिए चलना-फिरना मुश्किल हो रहा था। नुगी को इसके बाद एसपीसीए की देखरेख में रखा गया, लेकिन वह दो महीने के दौरान केवल 8.8 किलोग्राम (19.6 पाउंड) या उसके शरीर के वजन का लगभग 16.5 प्रतिशत ही कम कर पाया। और उसकी एक लिवर हेमरेज के कारण मौत हो गई। एसपीसीए ने इस मामले में कहा है कि कुत्ते को प्रतिदिन लगभग 10 टुकड़े चिकन के साथ ही सूखा भोजन दिया जाता था। जब वेटरनरियनों ने कुत्ते को उसके मालिक से दूर ले जाने की कोशिश की, तब नुगी मोटापे की वजह से मुश्किल से 10 मीटर चल पाया और सांस लेने के लिए तीन बार रुका। एसपीसीए ने कहा, उसके पैर उसके भारी शरीर का समर्थन नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से वेटरनरियनों को उसकी हार्टबीट भी सुनाई नहीं दे रहा था। कुत्ते के कोहनी और पेट पर कई तरह की गांठें थीं, और उसके पंजे भी बढ़े हुए थे। साथ ही नुगी को कंजक्टिवाइटिस भी था।

तालिबान ने विदेशों में कई अफगान मिशनों को किया अस्वीकार, पासपोर्ट और वीजा माने जाएंगे अवैध

काबुल , एजेंसी। अफगानिस्तान की राजनयिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिससे उनकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति और मान्यता पर प्रभाव पड़ा है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद कई अफगान राजनयिक मिशनों को बंद कर दिया। तालिबान ने उन देशों के साथ अपने राजनयिक संबंध खत्म कर दिए या उन देशों से अपने राजनयिक प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया जहां उनके मिशन स्थित थे। इसका मुख्य कारण तालिबान की सरकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली और कई देशों ने तालिबान के साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। तालिबान ने मंगलवार को कई अफगान राजनयिक मिशनों को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वे पूर्व पश्चिमी समर्थित प्रशासन द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को मान्यता नहीं देंगे। यह तालिबान का राजनयिक मिशनों पर नियंत्रण स्थापित करने का नवीनतम प्रयास है। तालिबान विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लंदन, बर्लिन, बेल्जियम, बॉन, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, ग्रीस, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, कनाडा और नॉर्वे में स्थित अफगान राजनयिक मिशनों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ अब मान्य नहीं हैं और मंत्रालय इन दस्तावेजों के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा।

मंत्रालय ने कहा कि इन प्रभावित दस्तावेजों में पासपोर्ट, वीज़ा स्टिकर, डीड्स और अनुमोदन शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन देशों में रहने वाले

लोगों को तालिबान के इस्लामिक एमीरात ऑफ अफगानिस्तान सरकार द्वारा नियंत्रित दूतावासों और काउंसलेट्स से संपर्क करना होगा। ÷सभी अफगान नागरिक और विदेशी नागरिक अन्य देशों में तालिबान के राजनीतिक और काउंसलर मिशनों से काउंसलर सेवाओं तक पहुँच सकते हैं,÷ ।

स्लोवाकिया के पीएम ने यूक्रेन को डीजल सप्लाई रोकने की दी धमकी

प्राग, एजेंसी। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने यूक्रेन को डीजल की सप्लाई रोकने की धमकी दी है। पीएम का कहना है कि यदि यूक्रेन के रास्ते स्लोवाकिया तक रूसी तेल का परिवहन जल्द ही फिर से शुरू नहीं किया गया तो देश की स्लोवनाफ्ट रिफाइनरी, यूक्रेन को डीजल की आपूर्ति बंद कर देगी। यूक्रेन ने हाल ही में रूसी कंपनी लुकोइल से ड्रूजबा पाइपलाइन के ज़रिए स्लोवाकिया और हंगरी तक तेल के परिवहन को रोक दिया था। उसने जून में कंपनी को अपनी प्रतिबंध लिस्ट में डाल दिया था। स्लोवाकिया के वित्त मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि लुकोइल से यूक्रेन के जरिए स्लोवाकिया को तेल की डिलीवरी पहले ही बंद हो चुकी है। एक वीडियो संदेश में कहा है कि यूक्रेन द्वारा लुकोइल पर लगाए गए प्रतिबंध को आगे लागू करने से यूक्रेन, स्लोवाकिया और हंगरी को ही नुकसान होगा। उन्होंने कहा, यदि यूक्रेन के माध्यम से रूसी तेल की आपूर्ति जल्द शुरू नहीं की गई तो स्लोवाकिया की कंपनी स्लोवनाफ्ट (जो यूक्रेनी खपत का दसवां हिस्सा कवर करती है) यूक्रेन को डीजल की आपूर्ति बंद कर देगी।

स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रकः- देवेन्द्र मालवीय द्वारा श्री सिंध्दी विनायक प्रिंटर्स 26 बी देशबंधु परिसर प्रेस काम्प्लेक्स झोन 1 एम पी नगर भोपाल म.प्र. से मुद्रित एवं 773 / 19 मेघदूत नगर इंदौर म.प्र. से प्रकाशित सम्पादक डॉ. देवेन्द्र मालवीय

कार्यालय पताः-एच. 21 अंकित अपार्टमेंट ब्रजेश्वरी एनएक्स, इंदौर मध्यप्रदेश मोः- 98276-22204 सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इंदौर रहेगा।

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त सूचनाए, विचार, आलेख विभिन्न समाचार के स्त्रोत एवं संकलन लेखकों के व संकलनकर्ता के स्वंय जिनका संकलन विभिन्न एजेंसियों, के माध्यम से किया गया है, अतः समस्त प्रकार के प्रकाशन हेतु संपादक, प्रकाशक, मुद्रक का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहमत होना अनिवार्य नही है।